bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org

संवत 2079 युगाब्द 5124 कुल पृष्ठ –45 अंक – 20

वर्तमान

कमल ज्योति

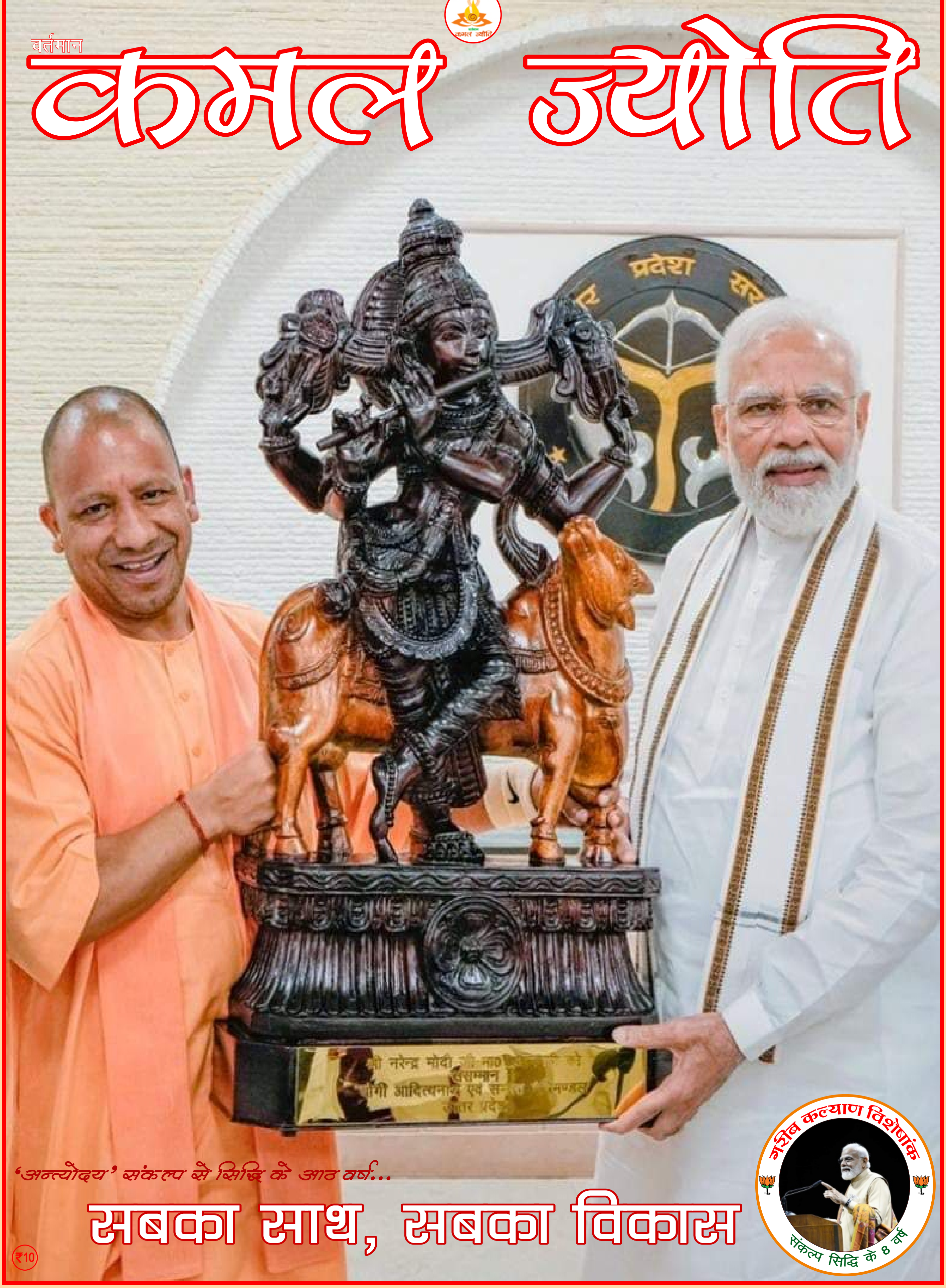

‘अन्त्योदय’ संकल्प से सिद्धि के आठ वर्ष...

सबका साथ, सबका विकास

गरीब कल्याण विशेषांक

संकल्प सिद्धि के 8 वर्ष

₹10

भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक
20 मई, 2022 (जयपुर)

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार

प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

अप्प दीपो भव:

नये भारत के शिल्पी नरेन्द्र मोदी : योगी

सम्पादकीय

सामाजिक सरोकार और भाजपा सरकार

विपदा एवं आपदा में मानव अपनी मूल वृत्तियों की रक्षा के रास्ते निकाल लेता है। ऐसी स्थिति में बहुधा हमारी सहनशक्ति और टकराव की वृत्ति मजबूत हो जाती है। इसके बीच में जन्म लेती है हमारे समाज में सेवा भाव की मजबूती। समाज के हर घटक समाज के दूसरे घटक को उबारने के लिये प्रयत्नशील हो जाता है। इसके बाद भी समाज के कुछ वंचित वर्ग ऐसे भी होते हैं जिनतक समाज का कोई घटक नहीं पहुंच पाता। ऐसा भी नहीं हैं कि, समाज अपने ही लोगों की चिंता नहीं करता है लेकिन भूलवश ऐसा हो जाता है। यहां से राजनीतिक सत्ता का कार्य आरंभ होता है। इसी दृष्टि के साथ भाजपा की सरकारें देशभर में कार्य कर रहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सामायिक दृष्टि के कारण समाज के अंत्योदयी वर्ग की पूरी चिंता की गई है जिससे इस वर्ग का विकास समासज के दूसरे वर्गों के अनुकूल बन सकें।

भारतीय समाज इस वर्ष भी गरीबी से उबरने के लिए संघर्ष करता रहा। इसके लिए सरकारें आजीविका सृजन से लेकर कौशल विकास के अनेक प्रयास कर रही हैं। यह जरूरी है कि हम उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा के स्नेतों की तलाश कर उन्हें लोगों के सामने लाना होगा।

प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के विज़न के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई जो उनके किये गये कार्यो में समाहित होती है। सरकार समाज के गरीब और वंचित वर्गों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से देश के सभी नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएं सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का पूरा ख्याल रखना है। पिछले आठ वर्षों में, समाज के सबसे गरीब व वंचित वर्गों तक सरकार की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में जबरदस्त तेजी आई है, चाहे वह बड़ी संख्या में बनाए गए घर (पीएम आवास योजना) हों, पानी के कनेक्शन (जल जीवन मिशन), बैंक खाते (जनधन), डीबीटी के जरिए किसानों को राशि का ट्रांसफर (पीएम किसान) या मुफ्त गैस कनेक्शन (उज्ज्वला) हो।

ऐसे में आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, मना रहा है। ऐसे समय में सरकार ने योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण में जनसहभागिता और नागरिकों के साथ जुड़ने के प्रयासों को तेज कर दिया है। इसके पीदे दिपि है भाजपा सरकारों की समवेशी राजनीति को स्थापित करने की मंशा जिससे समा के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है।

ऐसे में भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक–एक नागरिक की शक्ति में समाहित हो जाता है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को छह महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का जब निर्णय लिया तब देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों के चेहरों पर मुसकान खिल उठी। इस योजना पर सरकार की ओर से सितंबर तक होने वाले खर्चे की बात करें तो 3.40 लाख करोड़ व्यय हो रहे हैं।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशनकार्ड पर हर महीने मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है। राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इससे प्रदेश और देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे कि सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के वंचितों गरीबों के लिये असंख्य योजनाओं को आरंभ किया है जिससे प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। आज यह पूरे विश्व के लिये आश्यर्च का विषय है कि भारत अपने नागरिकों को संरक्षा और पूर्ण सुरक्षा देने में सक्षम है और यह सक्षमत आई है हमारे नेतृत्व के विचारों से उनके दृढीकरण से और उनक विवेकशीलता से। जिससे आज का भारत सक्षम और समावेशी धारा में आगे जा रहा है।

akatri.t@gmail.com

राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, जयपुर

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रधान सेवक 'नरेन्द्र'

2014 में, भारत के लोगों ने श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए में अपना विश्वास व्यक्त किया। 30 वर्षों के बाद भारत के लोगों ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर अपना आशीर्वाद दिया। 2019 में री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी और भाजपा की सीटों की संख्या 282 से बढ़कर 303 हो गई। किसी प्रधानमंत्री का अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हीं के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वापसी होना करीब 6 दशकों के बाद हुआ है।

2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी के पदभार ग्रहण किया, तो उन्हें पहले दिन से ही भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 का चुनावी जनादेश यूपीए सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस, भ्रष्टाचार और जबरदस्त वंशवादी राजनीति के बाद था। यूपीए के घेर कुशासन के कारण, भारत के लोग लोकतंत्र और सरकारों के काम करने की क्षमता में विश्वास खो रहे थे।

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को मिले विशाल जनादेश ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को फिर से जगाया है। इसने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि अगर एक निर्णायक, समावेशी और संवेदनशील नेतृत्व हो तो जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में, ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के दृष्टिकोण को साकार करने की आकांक्षा को प्रभावी और सुनियोजित तरीके से पूरा किया गया है। हृदय तल से सराहना... आभार!

135 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य और कौशल से संचालित और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र पर चलने वाली मोदी सरकार ने गरीबी दूर करने और देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कई पहल की है। मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के मंत्र के अनुरूप काम कर रही है, जिसका अर्थ है समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना।

श्री नरेन्द्र मोदी ने दिखाया है कि एक कुशल नेतृत्व क्या होता है। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता और शौचालय निर्माण जैसे विषयों पर बात की, जिसके बारे में पिछली सरकारें सोचती तक नहीं थी। पूर्ण स्वच्छता कवरेज सुनिश्चित करके उन्होंने महात्मा गांधी के एक सपने को भी पूरा किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में भारत की प्रगति के साथ कई अन्य सफलताएं भी प्राप्त हुई, जैसे इससे गरीबी के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई, स्वास्थ्य मानकों में सुधार हुआ और इससे पर्यटन के साथ–साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों में दृढ़ विश्वास दिखाते हुए मध्यम वर्ग के कई लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी और वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी रेलवे रियायतें छोड़ दीं, ताकि ये लाभ गरीबों को मिल सकें। कई दशकों तक भारत पर शासन करने वालों के भ्रष्टाचार के कारण ऐसी संस्कृति पहले देखी नहीं गई थी।

गरीबों को आश्रित बनाए रखने के बजाए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक ऐसी संस्कृति लाए हैं जो आत्मनिर्भरता, गरिमा और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। इसे 'मेक इन इंडिया' की सफलता, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की प्रगति, नीतिगत सुधारों और पीएलआई योजनाओं की सफलता में देखा जा सकता है। स्टार्ट–अप इकोसिस्टम में भारत की सफलता दर्शाती है कि कैसे भारत के युवाओं ने इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन में हमारे युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान केवल सरकारी नीतियों तक ही सीमित नहीं है। यह 135 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना को दर्शाता है जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ देखना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरूआत की है। उज्जवला ऐसी योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर गरीबों को आवास प्रदान करने के प्रगतिशील फेसलों में महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाया है।

कुल भारतीयों में से लगभग 2/3 कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन्होंने केवल कुछ बड़े किसानों पर ही ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही हैं जो छोटे किसानों के तारणहार बनकर उभरे हैं। पीएम–किसान योजना ने किसानों के वित्तीय बोझ को कम किया है, जबकि सिंचाई में सुधार और नीम–कोटिड यूरिया उपलब्ध कराने के प्रयासों से किसानों को काफी मदद मिली है। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के पीएम के दृष्टिकोण का कृषि–उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ा है। मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देने जैसे निर्णयों के मात्स्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं।

इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को दया और करूणा के प्रतीक के रूप में याद रखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुष्मान भारत पीएम–जय के कारण लाखों भारतीयों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। पीएम–बी0जेपी (प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना) ने सस्ती दवाएं सुनिश्चित की है, जिससे गरीबों, मध्यम वर्ग और निम्न–मध्यम वर्ग के लिए बड़ी बचत हुई है। स्टेंट और घुटना प्रत्यारोपण की कम कीमतों ने अनगिनत भारतीयों को नया जीवन दिया है।

मोदी सरकार के अंतर्गत ही भारत को 30 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। इस नीति का फोकस परिव्यय से हटकर परिणामों की ओर है। इस नीति की सुंदरता बड़े पैमाने पर परामर्श प्रक्रिया में निहित है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस नीति के साथ, भारत शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान का केन्द्र बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीानीय भाषाओं में शिक्षा की अनुमति देने और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि ने असंख्य आकांक्षाओं को पंख दिए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सबसे चिरस्थायी विरासतों में से एक यह है कि जिस तरह से प्रौद्योगिकी को सरकार के हर क्षेत्र में एकीकृत किया गया है, उससे लोगों को बुनियादी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती हैं। JAM (जनधन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) ने बिना किसी बिचौलिए के करोड़ों लोगों तक लाभ पहुंचाया है।

पिछली सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह थी कि प्रशासनिक कार्य साइलोज में होते थे। शासन में इन साइलोज को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष प्रयास किये हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण पीएम–गति शक्ति पहल है, जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के सपने को साकार करने के लिए प्रमुख आर्थिकी मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है। इसके अलावा प्रगति जैसी पहल जिसकी निगरानी सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है, ये लालफीताशाही और जड़ता को तोड़ने के नए तरीके हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन दशकों से हमारे देश के विकास पथ के लिए अभिशाप रहा है। इसे खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपना कार्यकाल समर्पित कर दिया है। पहली बार, आकांक्षी जिलों की अवधारणा को पेश किया गया था। जिसमें हाशिये पर छोड़े गए क्षेत्रों पर विस्तृत ध्यान दिया गया। अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, राष्ट्र आकांक्षी ब्लॉक्स की ओर देख रहा है। पूर्वोत्तर, जो पहले हिंसा और नाकेबंदी के लिए जाना जाता था, अब रिकॉर्ड विकास के लिए जाना जाता है। स्वयं प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा इस क्षेत्र के दौरे की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इस साल के केन्द्रीय बजट में सीमावर्ती क्षेत्रों और वहां के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत के तटीय क्षेत्रों पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है।

जिस समाज को अपनी जड़ों पर गर्व नहीं है, वह कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बार–बार इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत की ताकत हमारी विविधता, हमारे जीवंत विश्वास, भाषाएं, संस्कृतियां और रीति–रिवाज हैं। कई पुरावशेषों और कलाकृतियों को घर लौटते हुए देखना खुशी की बात है; इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खास दिलचस्पी ली है। कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सीनों को फिर से जीवंत किया गया है जो अधिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यह भारतीय संस्कृति में देशवासियों की दिलचस्पी बढ़ाएगा और सीनीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। इसका एक प्रमुख उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। संयुक्त राष्ट्र में तमिल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्द विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रति उनके स्नेह को दर्शाते हैं।

पिछले 8 वर्षों में, भारत ने पर्यावरण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती शुरू कर दी है। भारत का वन क्षेत्र बढ़ रहा है और इसी तरह शेरों, बाघों, गैंडों और तेंदुओं की आबादी भी।

इंटरनेशनल सोलर एलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सीपना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयास हमारे ग्रह को स्वच्छ और हरा–भरा बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। शुद्ध–शून्य उत्सर्जन पर COP-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धताओं ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी अंतराष्ट्रीय मंचों पर भी बहुत सराहना हुई। भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास एक साथ चल सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 'इंडिया फर्स्ट' विदेश नीति के अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक निवेश और लोगों से लोगों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव को फिर से परिभाषित किया है और उन्हें भारत के बाहरी संबंधों का

अभिन्न स्तंभ बनाया है।

वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था। दुनिया ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महामारी से लड़न के लिए हर कदम पर विज्ञान–संचालित दृष्टिकोण पर जोर दिया। शुरूआत से ही, वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय किए गए थे साथ–साथ राष्ट्र को Covid अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। भारत ने वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम शुरू किया और उन टीकों केसमय पर रोलआउट होने के कई लोगों की जान बच गई। महामारी के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिले।

7 अक्टूबर 2021 को, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 12.5 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 7.5 साल) पूरे किए। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति में यह एक विशिष्ट उपलब्धि है जिसे कुछ ही लोगों ने हासिल किया है। दूसरों की सेवा करने और अपने साथी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके निरंतर प्रयासों के कारण ही यह संभव हुआ।

हमें राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता पर गर्व महसूस होता है। जब हम भारतीयों के जीवन को बदलते हुए देखते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र को सशक्त बना रही है और समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है।

राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, जयपुर

लोकतंत्र में विजय ही विजय!

चार राज्यों में भाजपा की महाविजय – सफलता का एक और कदम

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत से एक बार फिर साबित हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के जनता की अगाध व अटूट आस्था है। उनकी नीति, नीयत एवं कार्यों पर जनता को पूर्ण विश्वास है और इस विश्वास को विपक्ष का कोई झूठा दुष्प्रचार तोड़ नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी की 'गरीब कल्याण और राष्ट्र प्रथम' की नीति तथा ''सबका साथ, सबका विकास'' का मूल मंत्र, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर भारी है। यह नतीजे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रो–पुअर, प्रो–एक्टिव और रेस्पोंसिव गवर्नेंस पर जनत के विश्वास की मुहर है।

चुनाव परिणाम में सारे मिथक और रिकॉर्ड टूटेः

उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद से 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक सरकार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, वह भी दो–तिहाई बहुमत से। साथ ही पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार वापसी की है। प्रदेश के 19 जिलों में भाजपा को छोड़ बाकी सभी पार्टियों का खाता भी नहीं खुला।

यूपी में पहली बार लगातार चार चुनाव – 2014 के लोक सभा चुनाव, 2017 के विधान सभा चुनाव, 2019 के लोक सभा चुनाव और अब 2022 के विधान सभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को प्रदेश की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा का वोट शेयर भी 39% से बढ़ कर 42% हुआ है। समाज के सभी वर्गों का पूरा सहयोग भाजपा को मिला है। किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में भी भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली है। इसका मतलब स्पष्ट है कि देश के किसानों को भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर ही भरोसा है।

उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद हर चुनाव में सरकार के बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन हमने इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड का चुनाव लड़ा और वहां भी सत्ताधारी दल के फिर नहीं जीतने का मिथक रिकॉर्ड बहुमत से तोड़ा। ये सब संभव हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक परिश्रम और गरीब कल्याणकारी सरकार के बल पर। मणिपुर में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई तो गोवा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, वह भी लगभग पूर्ण बहुमत से। उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भाजपा के मत प्रतिशत में वृद्धि हुई। सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य (उत्तराखण्ड), एक समुद्र तटीय राज्य (गोवा), एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त राज्य (उ0प्र0) और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य (मणिपुर)–भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न हैं लेकिन, एक सूत्र जो उभयनिष्ठ है, वह है – जनता का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पर अटूट विश्वास और भाजपा में आस्था।

इसके साथ ही, असम, त्रिपुरा, गुजरात, चंडीगढ़ आदि राज्यों में हुए सीनीय निकाय के चुनावों में भी जनता ने भाजपा को ऐतिहासिक विजय श्री दिलाई। त्रिपुरा सीनीय निकाय चुनाव में भाजपा को 334 सीटों में से 329 सीटों पर ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। भाजपा की जीत का प्रतिशत 98.50 रहा। इसी तरह असम के सीनीय निकाय चुनाव में कुल 997 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 807 सीटें मिली। भाजपा गठबंधन की जीत का प्रतिशत 82.60% रहा। भाजपा को इस चुनाव में अकेले 742 सीटें मिली जबकि हमारे सहयोगी को 65 सीटें मिली। इसी तरह गुजरात में गांधीनगर, थारा, ओखा और भानवड़ नगर पालिका में

भाजपा को एकतरफा जीत मिली। चारों नगर पालिका को मिला कर भाजपा को कुल 128 सीटों में से 103 सीटें मिली और भाजपा की जीत का प्रतिशत 80 से अधिक रहा। गुजरात में सीनीय निकाय के उप–चुनावों में भी भाजपा ने परचम लहराया है। नगर निगम की तीन सीटों में से 2, जिला परिषद की 8 में से 5, तहसील परिषद की 45 मे से 28 और नगर पालिका की 45 में से 37 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। इस तरह इन उप–चुनावों में भाजपा को 101 में से 72 सीटें मिली। चंडीगढ़ नगर निगम में भी भाजपा ने वापसी की । दो दिन पहले ही केरल के पंचायत चुनाव में प्रदेश की एक मात्र आदिवासी वार्ड में भी भाजपा को जीत मिली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक भाजपा को केवल बहुमत नहीं मिल रहा बल्कि अपार समर्थन मिल रहा है और यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व और उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार की जनता के लिए सेवा एवं समर्पण की नीति का परिणाम है।

प्रो–इनकम्बेंसी –

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गरीब कल्याण कार्यों व नीतियों एवं सुशासन ने देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एंटी–इन्कंबेंसी जैसे फैक्टर के सीन पर 'प्रो–इन्कंबेंसी फैक्टर' तैयार कर दिया। इसीलिए भाजपा के पक्ष में जाति–पाति के बंधनों से बाहर आकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों आदिवासियों, किसानों, युवाओं और महिला मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया। शासन, प्रशासन और विकास अब केन्द्रीय भूमिका में आने लगा है। योजनाओं की घोषणा के बजाय उन्हें जमीन तक पहुंचाने की कवायद, अब चर्चा में शामिल हो गई है।

बड़े–बड़े दावे करने वाले लोगों की ऐतिहासिक पराजय –

यह भी पहली बार हुआ कि जिस पार्टी ने यूपी में लगभग 40 साल तक शासन किया और देश में आजादी के लगभग 55 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी यूपी में 399 में से 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने यूपी में 377 सीटों पर चुनाव लड़ा, हर सीट पर उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। उत्तराखण्ड में भी 'आप' की 70 में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। गोवा में आप के साथ–साथ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की भी ऐतिहासिक पराजय हुई। इसके साथ ही इन चुनावों में तथाकथित राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण और एग्जिट पोल्स की भी हार हुई। तमाम एग्जिट पोल्स और तथाकथित राजनीतिक पंडित उत्तराखण्ड और गोवा में भाजपा की सरकार की विदाई की बात कर रहे थे, लेकिन जनता के निर्णय के आगे सभी के गणित फेल हो गये।

मुश्किल समय में जनता का साथ –

कोरोना के समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार और सभी भाजपा शासित राज्य सरकारें, विपक्ष के दुष्प्रचारों पर कोई ध्यान न देते हुए लगातार जनता की सेवा में लगी हुई थी, जबकि पूरा का पूरा विपक्ष क्वारंटाइन हो गया था। प्रधानमंत्री जी के 'सेवा ही संगठन' के आहवान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मानवता की सेवा में अपने आप को झोंक दिया। जरूरतमंदों को आर्थिक मदद दी गई, रोजगार उपलब्ध कराया गया, गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत की शुरूआत हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता को विपक्ष के भ्रामक झूठ पर विश्वास नहीं रहा और विपक्ष की साख भी जनता की नजरों में गिरती चली गई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से सबको कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के साथ ही समुचित इलाज के प्रयत्न भी प्रमुख कारण है, जिसे लोगों ने महसूस किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज एक ऐसी सरकार है जिसकी सभी

योजनाओं का ध्येय विकास की दौर में पीछे छूट गए समाज के Marginalized Sections का अंत्योदय है।

ऐतिहासिक जीत के प्रमुख कारक –

मोदी जी के संकल्प और कार्यों ने नए भारत के निर्माण के लिए जाति–पंथ की सीमा से परे एक 'लाभार्थी' वर्ग और एक नया 'एम–वाई समीकरण' अर्थात 'महिला व युवा एवं योजना' का समीकरण तैयार कर दिया। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, दो साल से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना, जन–धन योजना, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसान सम्मान निधि, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, फसल बीमा योजना जैसे अनेक कार्य ऐसे रहे कि मोदी जी पर जनता का विश्वास बढ़ता ही गया। यही कारण है कि

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में भाजपा को पारंपरिक मतों के साथ ही 46 प्रतिशत महिलाओं का मत भी मिला। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना ने भारत में गरीबी को 1ः से कम रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के बावजूद देश में अत्यधिक गरीबी को दर 0.8% पर ही स्थिर है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण पिछले 8 वर्षों में भारत में लगभग 12.3% से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी के दायरे से निकले। मुश्किल समय में भी देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के कटिबद्ध भाव से समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हम अभिनन्दन करते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर लहराया भाजपा का परचम

बात केवल इस बार हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत की नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश में हुए हर चुनाव ने भाजपा के लिए एक नया कीर्तिमान सीापित किया है। चाहे वह विधान सभा चुनाव हो, विधान सभा के उप–चुनाव हो या फिर सीानीय निकाय के चुनाव, हर चुनाव में भाजपा ने जनता का अपार समर्थन प्राप्त किया है।

कोरोना कालखण्ड के समय से लेकर इस बार के विधान सभा चुनाव से पहले तक बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, केरल और तमिलनाडु में विधान सभा चुनाव हुए थे। बिहार में जहाँ भाजपा ने सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ 110 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 74 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार पुनः सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 3 से 77 तक का सफर तय किया और मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को स्थापित किया। असम में पुनः भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाई। तमिलनाडु में भाजपा ने पहले से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा किया है। इसका लाभ हमें तमिलनाडु के सीानीय निकाय के चुनाव में भी मिला है जहाँ हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। केरल में भी हम सही दिशा में जा रहे हैं।

बात करें विधानसभा उप–चुनावों की तो 2020 से देश में लगभग 15 राज्यों में 100 से अधिक सीटों पर उप–चुनाव हुए, उनमें से 60 से अधिक सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा ने तेलंगाना की दुब्बका और हुजूराबाद में असंभव को संभव कर दिखाया और 200 वोटों से जीत तक का सफर तय किया। ये चुनाव परिणाम तेलंगाना की परिवारवाद व तुष्टिकरण की राजनीति पर करारा प्रहार है। गुजरात में हमने गुजरात 8 की 8 विधान सभा सीटों पर चुनाव जीता । इसी तरह हमने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और बिहार में हुए उप–चुनावों में भी जीत दर्ज की।

2020 से देश के अलग–अलग राज्यों में हुए सीानीय निकाय के चुनावों में भी जनता का भरपूर आर्शीर्वाद भाजपा को मिला। सीानीय निकाय के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये जमीनी हकीकत से हमें परिचित कराते हैं। चाहे लद्दाख ऑटोनोमस मिल्स के चुनाव हों, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 से 49 सीटों पर जीत का सफर हो, जम्मू–कश्मीर के बीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा का उभरना हो या फिर राजस्थान के ग्रामीण निकाय के चुनाव में भाजपा की जीत कापरचम लहराना हो, अरूणाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव हों, असम के बीटीसी चुनाव हों, गोवा जिला पंचायत चुनाव हो या फिर गुजरात नगर निगम के चुनाव – हर चुनाव में जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को दिया है।

दुर्गम राजनीतिक क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने Front से Lead कर भारतीय जनता पार्टी को अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक जीत दिलाई है, इसके लिए भाजपा उनका हार्दिक धन्यवाद करती है।

नीति, नियत, निश्चय और निर्णय के आठ वर्ष

कर्तव्य दायित्वों के निर्वाहक : नरेन्द्र मोदी

सदी के प्रारम्भ में जब भविष्य वाणियाँ होती थी कि 21वीं सदी भारत की होगी पर जब प्रधान सेवक नरेन्द्र मोदी गरीब, मजबूर व्यक्तियों के सेवके रूप में सांस्कृतिक भारत के दूत स्वरूप में मोदी जी ने दुनिया में वसुंधैव कुटुम्बकम के भाव से कार्य किया तो तय हो गया कि विश्व का कल्याण भारत की सोंच सबका साथ, सबका विकास से ही होगा। जिसके वाहक नरेन्द्र मोदी होंगे।

रामचरित मानस में प्रभु श्रीराम के भक्तों के बारे में बहुत ही सटीक बात कही गई है–

"प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई।
हारहिं सकल सलभ समुदाई"।।

अर्थात् भगवान श्री राम के आर्शीवाद से, उनके अनुसरण से अविद्या, अज्ञान और अंधकार मिट जाते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो हर जाती है और भगवान श्री राम के अनुसरण का अर्थ है–मानवता का अनुसरण, ज्ञान का अनुसरण!

वर्तमान सरकार इसी पथ पर चल रही है। मोदी सरकार का यही मूल मंत्र है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 30 मई 2019 को लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके दूसरे कार्यकाल की शुरूआत की। 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जघन्य हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के भरोसे स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने लोकसभा में 400 से भी अधिक सीटें प्राप्त की थीं और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें प्राप्त हुई थीं। भाजपा की उपस्थिती उस समय लोकसभा में नगण्य थी। फिर ऐसा क्या हुआ? कांग्रेस नेपथ्य में चली गई और भाजपा दो सीओं से क्रमशः बढ़ते–बढ़ते तीन बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल हुई। भाजपा यहां रूकी नहीं, न थकी, न हारी, न सिद्धांतों से समझौता किया, 2014 में चमत्कारिक नेतृत्व, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई। इसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ? सरकार में रहने वाली पार्टी को तो जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, पर 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और बड़े बहुमत से सरकार बनाते हैं।

कहानी यहां रूकती नहीं है, 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 55 के आसपास थी। फिर ऐसा क्या होता है कि भाजपा राज्यसभा में 100 सदस्यों से अधिक सदस्यों की पार्टी बन जाती है। राजनैतिक पंडित जोर–जोर से घोषणा कर रहे हैं कि 2022 खत्म होते–होते भाजपा राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत पा जायेगी।

सोचिए क्या यह चमत्कार है, या भाजपा को जनता के द्वारा दिया गया उपहार?

ऐसा नहीं है, यह कोई उपहार नहीं है इसके पीछे सतत् संघर्ष से भरा हुआ इतिहास है। राजनैतिक स्पष्टवादिता है, विपरीत परिस्थितियों में भी सिद्धांतों से समझौता न करने का अटूट विश्वास है, राजनैतिक प्रतिबद्धता है, लोकतंत्र व राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सम्पूर्ण भारत के लिए एक भाव है। जाति, धर्म, भाई–भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ शंखवाद है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। भारत माता की गोद में पलने वाला हर भारतवासी भारतीय है और वो हमारा अपना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हर भारतीय के भाई हैं, संरक्षक हैं। यह अटूट विश्वास शब्दों से नहीं आया है, भाषणों में नहीं आया, कार्यक्रमों में नहीं आया। भाषण,

शब्द और कार्यक्रम तो और नेता भी प्रयोग में लाते रहते हैं। पर इस अटूट विश्वास को श्री नरेन्द्र मोदी जी लाने मे ंक्यों सफल रहे, यही यक्ष प्रश्न है। इसको इस तरह समझिये, इसके लिए श्री नरेन्द्र मोदी जी की कार्यशैली का इतिहास समझना पड़ेगा। श्री नरेनद्र मोदी जी का जन्म किसी राज परिवार में नहीं हुआ था।

17 सितम्बर 1950 को गुजरात के बड़नगर मे ंएक बेहद गरीब परिवार में जन्में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबों के दुख–दर्द, तकलीफ, बीमारी, आर्थिक परेशानी जैसी तमाम समस्याओं को बेहद करीब से देखा है, अनुभव किया है और यहीं से इन समस्याओं के खिलाफ शंखवाद किया है, और अपने व्यक्तित्व को निखार दिया है।

कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सम्पूर्ण भारत के लिए एक भाव है। जाति, धर्म, भाई-भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ शंखवाद है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। भारत माता की गोद में पलने वाला हर भारतवासी भारतीय है और वो हमारा अपना है।

अब समस्या श्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए समस्या नहीं हैं, श्री नरेन्द्र मोदी जी समस्या के एि समस्या हैं। इतनी परिपक्वता, विशाल अनुभव और दूरदृष्टि, मातृभूमि के लिए समर्पण, हर भारतवासी तो भाई है ही, हर माता–बहन दैवीय स्वरूप है। बात यहां खत्म नहीं होती श्री नरेन्द्र मोदी तो ''वसुंधैव कुटुम्बकम'' का पालन करते हैं, इसी प्रकार आज पूरे विश्व केक सर्वमान्य नेता हैं। सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, सबका भरोसा हैं। हर सोंच के पीछे ''इंडिया फर्स्ट'' की भावना बनी रहती है। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी यात्रा प्रारम्भ करके फिर 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया। ईमानदारी भी इस स्तर की, पारदर्शिता का स्तर भी इतना स्पष्ट की कोई विरोधी भी शक जाहिर नहीं कर पायें।

सरकारें तो आती और जाती रहती हैं। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी का स्थाई अधिकार नहीं होता। मालिक तो मतदाता होता है। मतदाता की मर्जी से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है।

मोदी जी के मामले में थोड़ा सा फर्क है।

मोदी जी के ऊपर मतदाताओं का अटूट विश्वास, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए ड्रायविंग फोर्स का काम करता है। मोदी जी का नाम उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसा क्यों?

प्रधानमंत्री तो, मोदी जी से पहले भी कई हुए हैं। फिर मोदी जी ही जनता के केन्द्र में क्यों? वास्तव में विपक्ष के पास मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं है। 2001 में जब मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब भुज भीषण भूकम्प की तबाही को झेल रहा था, कई सारी चुनौतियां थी, इन चुनौतियों के बाद भी मोदी जी भुज को फिर से खड़ा करने में सफल हुए। भूकम्प के कारण भीषण आर्थिक तबाही हुई थी पर मोदी जी ने न केवल गुजरात को फिर खड़ा किया बल्कि केन्द्र के असहयोगात्मक रवैये के बावजूद गुजरात देश का वो राज्य था जहां निवेश सबसे अधिक आया। गुजरात निवेश के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया। निवेश और निवेशक को मोदी जी के नाम का, काम का,

विश्वास का भरोसा था। यही बात तो मोदी जी को दूसरों से अलग खड़ा कर देती है और यही तो मोदी जी की सच्ची पूंजी है।

गुजरात देश का वो पहला राज्य बना जहां 24 घंटे बिजली का नया कॉनसेप्ट जनता ने देखा। पहले बिजजी आती थी यह समाचार होता था, अब मेन्टेनेंस के लिए बिजली बाधित हुई यह समाचार बनने लगा। यह फर्क मोदी जी ने लाया। माता–बहनों का आर्शीवाद पहली बार किसी राजनैतिक दल को इतने विराट स्वरूप में मिला, कई राजनैतिक मित्र तो कहते हैं कि माता–बहनों के वोट तो मोदी जी के स्थाई वोट हैं। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दिन–प्रतिदिन इन वोटों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण भी बहुत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने 2004 में ''कन्या केलवणी'' योजना और ''शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम'' प्रारम्भ किये। 2005 में मोदी जी ही वो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इसका बहुत लाभ मिला। देश में मातृ शक्ति के सम्मान, सशक्तिकरण का यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान सिद्ध हुआ। महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए तथा परिवारों को विघटन से बचाने के लिए मोदी जी ने गुजरात में पूर्ण शराब बंदी लागू करी। शराब का सबसे ज्यादा प्रकोप अत्याचार के रूप में महिलाऐं झेलती हैं। परिवार विघटन का सबसे बड़ा दर्द भी महिलाऐं ही झेलती हैं। शराब में खर्च हुआ पैसा, स्वास्थय एवं परिवार के संस्कारों में होने वाले ह्रास का, प्रकोप का, दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को ही होता है। मोदी जी के इस एक ही निर्णय से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। एक ही बार में। मोदी जी यहां रूकने वाले कहां थे, गुजरात ही शायद देश का वो पहला राज्य है जिसने महिला सशक्तिकरण एवं परिवार को टूटने से बचाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किये। प्रापर्टी की रजिस्ट्री महिला के नाम निःशुल्क करना प्रारम्भ किया। महिला सशक्तिकरण का यह कितना बड़ा निर्णय था। अब महिला कमजोर नहीं बल्कि घर की सम्पत्ति की मालकिन थी। उसके सम्मन में, उसके चेहरे पर खुशी कितने गुना बढ़ी यह समझ से परे है। तभी तो मातृ–शक्ति की हर आवाज पर मोदी जी के लिए आर्शीवाद ही निकलता है। अभी भी कहानी यहां रूकी कहां।

मोदी जी ने महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या घर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की, जो गुजरात में माना जाता था कि यह कभी ठीक हो ही नहीं सकती। मोदी जी ने इसे मिशन मोड में लेकर घर–घर मीठा पानी पहुंचाने का अकल्पनीय प्रयास किया। जलस्तर को उठाया, बरसात के पानी को पूरे गुजरात में पहुंचाया, पानी संग्रहित किया, पीने का पानी, खेती, जानवर सब के लिए व्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में भी उठाल आया। रोजगार भी बढ़ा। बरसों से पानी की समस्या समाधान के लिए मोदी जी का इन्तजार कर रही थी। मोदी जी आये और हमेशा–हमेशा के लिए समाधान कर दिया।

महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए। आर्थिक फ्रंट पर महिलाओं के सम्मान को न केवल बढ़ाया बल्कि मातृ शक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की। तभी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण में बैंकिंग सुविधाऐं, जन–धन खाते के माध्यम से जोड़ी हालांकी इतनी बड़ी संख्या में खाते खोलना बड़ी चुनोती थी। आजादी के 67 वर्ष में भी जिन्होंने बैंकिंग के बारे में नहीं जाना था, उनकी समस्या का समाधान बहुत बड़ा काम था और चुनौती को मोदी जी ने मिशन के रूप में लिया और योजना प्रारम्भ होन के मात्र प्रथम वर्ष में ही 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गये। जिसमें से 1,80,96,130 बैंक खाते एक सप्ताह में खेलने का गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इन जन–धन खातों के कारण ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सफल करना आसान हुआ। अब महिलाएं बचत करने में भी सफल हुई। जन–धन खातें में जमा पूँजी भी हजारों करोड़ रूपये को पार कर गई। मोदी जी ने महिलाओं को बैंकिंग से तो जोड़ा ही साथ–साथ वक्त बे वक्त के लिए पूँजी भी जमा करवा दी। जन–धन योजना केक कारण बैंकिंग के साथ–साथ डिजिटल ट्रांजेक्शन का भी पूरे देश भर में विस्तार हुआ। 2013–14 में डिजिटल ट्रांजेक्शन 247 करोड़ था, विगत 7 वर्षों में इसमें 28 गुना बढ़ोत्तरी हुई। 2020–21 में यह 7,100 करोड़ हो गई। 45.11 करोड़ से अधिक जन धन खातों में 1.60 लाख करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है। जन धन खातों में महिला खाताधारकों की संख्या 25.11 करोड़ है अर्थात लाभार्थियों में लगभग 56 प्रतिशत महिलाएं हैं। कोरोना काल में

महिलाओं के खाते में पैसा जमा करना बिना एक पैसे के लीकेज के सम्भव हुआ। यही तो मोदी जी चाहते थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में सब्सिडी जो बैंक खातों में सीधे जमा कराई उससे लीकेज और हेराफेरी की गुंजाइश तो समाप्त हुई ही साथ ही एलपीजी सब्सिडी के 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान हुई और उन्हें बंद करके टेक्स पेयर के हजारों करोड़ रूपये बचाने मे सफलता मिली। भ्रष्टाचारियों के टारगेट पर मोदी जी क्यों बने रहते हैं, इसका कारण भी स्पष्ट है। आखिर खजाना लूटने से कोई रोकेगा तो लुटेरों के प्रतिशोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर माता–बहनों के आर्शीवाद से लुटेरे प्रतिशेध भी नहीं ले पाये। अब मौके की तलाश में बिल्ली की तरह बैठना मजबूरी है। क्या करें मोदी जी को कैसे घेरें? इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। क्योंकि मोदी जी सरकार गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीढ़ितों माता–बहनों के लिए चला रहे हैं। मोदी जी के विचार–मोदी जी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और विचार भी इतने मजबूत की फेल होने की कोई संभावना ही नहीं। यही तो मोदी जी हैं।

स्वास्थ्य परिवार का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। परिवार का कोई भी सदस्य इस समस्या से अछूता नहीं रह पाता और इस समस्या का प्रकोप घर की महिलाओं को सर्वाधिक झेलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लाकर 50 करोड से अधिक भारतीयों को कवर कर के गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ करवाई। सोंचिए 50 करोड़ तो कई देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं है और मोदी जी ने देश को इतना सशक्त, सामर्थ्यवान बना दिया है, इतना सक्षम बना दिया है कि आज 50 करोड़ नागरिकों के इलाज की भारत के प्रधानमंत्री की गारण्टी है। वो भी पूर्णतः निःशुल्क। अब गरीब इलाज के लिए मोहताज नहीं, इलाज के लिए ऋण लेना नहीं पड़ता, साहूकार के चंगुल में फंसना नहीं पड़ता, घर बेचना नहीं पड़ता, भगवान के भरोसे छोड़ देना या अब तो मौत के साथ ही बीमारी जायेगी– कोई भी बात नहीं क्योंकि मोदी जी ने फ्री में उच्च गुणवत्ता के इलाज की गारण्टी दी है और मोदी जी की गारण्टी तो पत्थर की लकीर है।

2016 में प्रधानमंत्री जी ने न केवल महिलाओं बल्कि पूरे परिवार के लिए अभूतपूर्व योजना की घोषणा करी। जिस देश में खाना पकाने की एलपीजी गैस ब्लैक में बिकती हो, गैस सिलेन्डर पर राशनिंग भी देश ने झेली है, एक वर्ष में 12 सिलेण्डर मिलेंगे या फिर 6 मात्र? उस देश में गरीबों को मुफ्त रसोई प्रदान करना अकल्पनीय या भागीरथी प्रयास है। इस प्रयास से सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलायें हैं। रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन माता बहनों के लिए मोदी जी की सौगात है। क्योंकि यह मोदी जी ही हैं जिनको गरीब माता बहनों के स्वास्थ्य की चिन्ता थी। उनके दर्द का एहसास था।

जिस देश में आजादी के 70 साल बाद भी 18000 गाँव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। लक्ष्य बना कर विद्युतीकरण का कार्य किया गया और शत–प्रतिशत सफलता हासिल की गई। फिर से महिलाओं का आर्शीवाद मिल गया। अब चिमनी के धुऐं में नहीं जीना पड़ता, एलईडी बल्ब भी मोदी जी ने पहुँचा दिया।

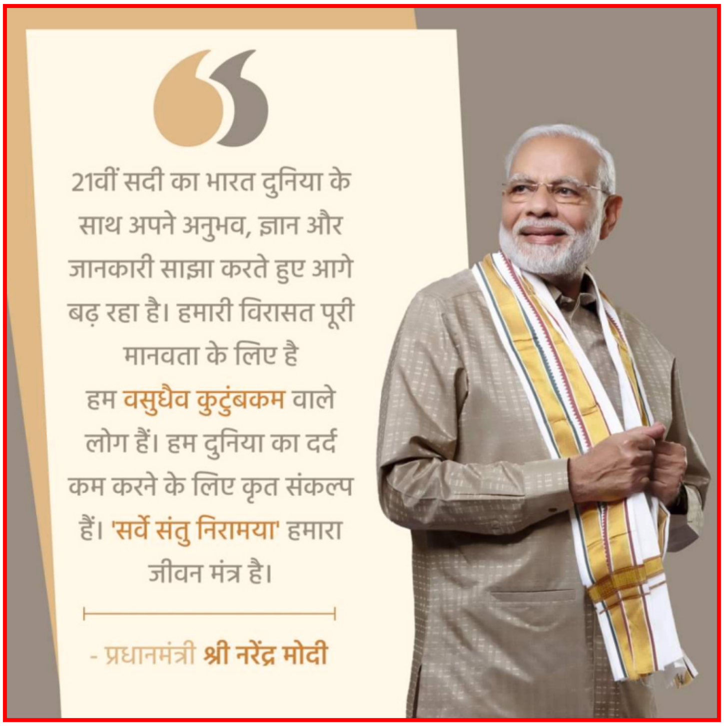

बेघर भारतीयों को देख कर मोदी जी को कितना दर्द होता होगा यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बेघर होने के कारण महिलाओं को कितनी समस्या होती थी और भगवान ने भी इस समस्या के समाधान के लिए मोदी जी को ही चुन करके रखा था। तभी तो 2014 से 2022 तक प्रधानमंत्री जी के हाऊसिंग फॉर आल के सपने को पूरा करने के लिए सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है। अब बेघर गरीब महिलाऐं बेघर नहीं, गरीब नहीं लखपति हो गई हैं।

स्वच्छता की कमी के कारण होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को पूज्य बापू जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन प्रारम्भ किया। इस जन आंदोलन को इतना अच्छा जन समर्थन मिला कि 2014 में जो स्वच्छता कवरेज 38 प्रतिशत था आज 99 प्रतिशत हो गया है।

शायद देश के इतिहास की यह पहली सरकार है जहां मातृ–शक्ति इतनी बड़ी संख्या में इतने महत्वपूर्ण पदों पर है। महिलाओं के हितों के लिए भाषण तो कई नेताओं ने दिये पर जब केन्द्र सरकार में पद देने की बात आती थी तो बात बदल जाती थी। यह मोदी जी ही हैं जिन्होंने देश की सरकार मातृ शक्ति को साथ लेकर चलाई है। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश की अनुमति दी। आज महिलाये सेना में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। खुले में शौच न केवल स्वास्थ्य को नुकसान देता है बल्कि

महिलाओं केक लिए तो बहुत ही चुनौती पूर्ण कार्य था। प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश को खुले में शौंच से मुक्ति दिलाई बल्कि महिलाओं के आत्म सम्मान और गौरव की रक्षा करने में भी सफल रहे। घर–घर शौचालय का निर्माण करवाया। स्वच्छता भी आई–सम्मान की रक्षा भी हुई–क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।

पीने का स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाना विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक हर घर तक नल से जल का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है और लक्ष्य मोदी जी ने निर्धारित किया है, इसलिए पूरा तो होगा ही। तभी तो महिलायें मोदी जी को दोनों हाथों से आर्शीवाद देती हैं और प्रभु से मोदी जी के लिए प्रार्थना भी करती हैं क्योंकि मोदी जी हैं जिन्हें समस्या बताना नहीं पड़ती, मोदी जी स्वयं समस्याओं को खोज कर उसका समाधान करने में जुट जाते हैं। तभी तो समस्याऐं मोदी जी से डरती हैं। कौन सी समस्या ऐसी हैं, जो मातृ–शक्ति को परेशान कर सके और मोदी जी ने उसका समाधान न किया हो। ऐसा सम्भव नहीं है। मुस्लिम बहनों के तीन तलाक का दंश भी मोदी जी ने एक ही निर्णय से खत्म कर दिया। वोट बैंक की राजनीति में वोट तो लिए गये थे पर कभी उनके दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया था। नेता जोर–जोर से चिल्ला कर भड़काने व अपनी गोटी लाल करने का कार्य तो बेरोकटेक करते थे पर तीन तलाक की धार पर जीने को मजबूर करके छोड़ दिया था। मोदी जी आये और तीन तलाक की तलवार ही गायब कर दी, हमेशा–हमेशा के लिए खत्म कर दी। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी। आज देश अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करता है और उसे हासिल भी करता है। इस देश ने शिलान्यासों की पट्टियां तो बहुत देखीं पर देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो शिलान्यास के वक्त स्वयं ही उद्घाटन करने का वादा करके जाते हैं और अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही उद्घाटन भी करते हैं। अब शिलान्यास कर जनता को मूर्ख बनाने का दौर खत्म हो चुका। अब उद्घाटन कर देश को समर्पित करने का दौर आ चुका है। मोदी जी ने ऐसे नेताओं के भविष्य के रास्ते भी बन्द कर दिये। कोरोना के भीषण महामारी के दौर में जब पूरा विश्व लड़खड़ा गया था, आज भी सोंच कर डर लगता है कि अगर उस दौर में मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो इतने विशाल देश का क्या होता?

गंभीर आर्थिक चुनौतियों के बावजूद समय पर लाकडाऊन का साहसिक निर्णय, स्वदेशी वैक्सिन का निर्माण, 135 करोड़ भारतीयों को डबल वैक्सिनेशन करवाना, गरीब महिलाओं के खातों में पैसे डालना, कोई भी गरीब भूखा न सोए, 80 करोड़ भारतीयों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, यहां भी नहीं रूके मोदी जी, पराक्रम की पराकाष्ठा करी। ''वसुंधैव कुटुम्बकम'' का पालन करते हुए पूरे विश्व तक वैक्सिन पहुँचाई। क्या कुछ नहीं किया?

बिल्कुल सही है, मोदी जी को समझ पाना संभव नहीं है, यह ही एक साथ सारे फ्रंट पर स्वयं ही मोर्चा संभाल कर देश को बचाने–आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। भीषण महामारी का दौर भी निकल गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को देश में कहीं भी अन्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई। देश के गरीब लोगों खासकर प्रवासी मजदूरों के साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़े रह कर मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि इतनी बड़ी महामारी के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज पहुँचे, यह कुशल प्रबन्धन न केवल सराहनीय है बल्कि अंर्तराष्ट्रीय पटल पर भी प्रधानमंत्री जी के कार्यों को सराहना मिली। इन प्रयासों से महामारी के बावजूद देश में न तो गरीबी बढ़ी, न असमानता बढ़ी, बल्कि गरीबी घट गयी।

1984 में सिख नरसंहार में पीड़ित सिख भाईयों के दर्द पर मरहम लगाने का कार्य मोदी जी ने किया। दरिन्दगी करने वालों को जेल में डाला। एसआईटी जाँच बैठाई, दोषियों पर कार्यवाही करी। जबकि देश ने देखा है कि सिख नर संहार में शामिल लोग पिछली सरकारों में सिर उठाकर घूमते थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सिख नरसंहार के पक्ष में बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। जिम्मेदारी से बचने का कितना आसान तर्क था। आज भी सोंच कर डर लगता है कि भारत को ऐसा नेतृत्व भी मिला था।

देश के संविधान निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी समेत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नजर अंदाज कर परिवार की संतुष्टि के लिए चुनिंदा नामों को इतिहास बनाने का प्रयास हुआ, मोदी जी ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी समेत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान प्रदान कर सही इतिहास देश के सामने लाने का प्रयास किया है आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के इस निर्णय से देश को बेहतर ढंग से समझने में सफल होंगी।

अब आक्रांता महान नहीं होंगे, महान होंगे इस मातृ भूमि के लिए हंसते–हंसते अपने प्राण न्योछावर करने वाले भारत के वीर सपूत वीरांगनाऐं। जिन्होंने मातृ भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और सरकारों ने उन्हें उचित सम्मन भी नहीं दिया पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आजादी के अमृत काल में सभी को सम्मान मिल रहा है। देश की रक्षा करते–करते अपने प्राण न्योछावर करने वाले प्रत्येक सैनिक का नाम भी अब वार–मेमोरियल में अंकित है, उनका परिवार अब बेसहारा नहीं, मोदी जी का सहारा है। वार–मेमोरियल में अंकित नाम अब हर सैनिक परिवार के सम्मान को ऊँचा कर रहा है, उन्हें गर्व है कि मातृ भूमि की रक्षा के लिए दिये गये बलिदान पर भारत को गर्व है। भविष्य जब मोदी जी को पढ़ेगा तो पूरा विश्व मोदी जी को सामान्य मानव मानने को तैयार ही नहीं होगा। मोदी जी को समझ पाना संभव ही नहीं है। इतनी दूर दृष्टि, इतना समर्पण, इतना विशाल नेतृत्व, इतनी क्षमताएं भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रभु श्री राम का आर्शीवाद है और धन्य है इस देश की जनता जिसने मोदी जी को अपने नेता के रूप में चुना, धन्य है यह देश जिसे मोदी जी का नेतृत्व मिला।

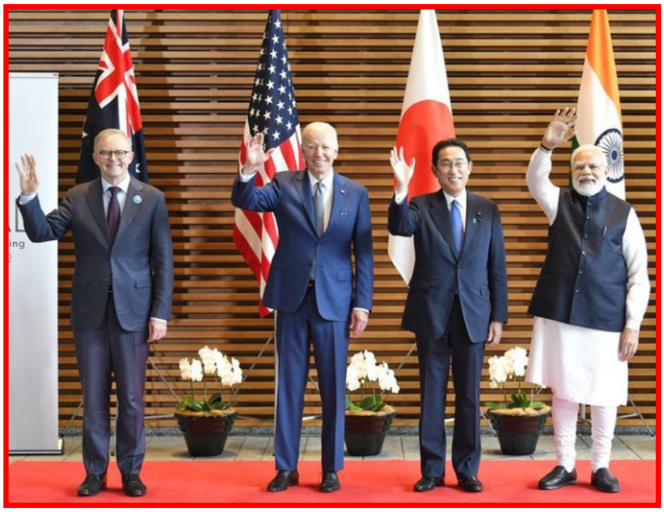

आतंकवाद हिंसक उग्रवाद निन्दनीय : मोदी

प्रधानमंत्री वर्तमान में विश्व के मन्य नेता स्वीकर होते जा रहे हैं। टोकियो के क्वॉड सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा कि हम ठीक एक साल पहले, नेता पहली बार मिले थे। आज टोक्यो में, हम अपनी चौथी बैठक के लिए और व्यक्तिगत रूप से दूसरी बार गंभीर वैश्विक चुनौती के समय यह प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए हैं कि क्वाड अच्छे के लिए एक ताकत है, इस क्षेत्र में वास्तविक फायदे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहयोग के अपने पहले वर्ष में, हमने सकारात्मक और व्यावहारिक एजेंडे के लिए क्वाड के समर्पण को स्थापित किया; अपने दूसरे वर्ष में, हम इस क्षेत्र को 21वीं सदी के लिए और अधिक लचीला बनाने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कोविड–19 महामारी के कारण दुनिया अभी भी मानवीय और आर्थिक पीड़ा को झेल रही है, देशों के बीच एकतरफा कार्रवाई की प्रवृत्ति और यूक्रेन में एक दुःखद संघर्ष चल रहा है, हम अडिग हैं। हम स्वतंत्रता, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करते हैं, धमकी या बल प्रयोग के बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास और नौवहन तथा किसी स्थान के ऊपर से उड़ने (ओवरफ्लाइट) की स्वतंत्रता, सभी का समर्थन करते हैं जो सभी हिंद–प्रशांत क्षेत्र और दुनिया की शांति, स्थिरता तथा समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। हम इन सिद्धांतों को क्षेत्र और उसके बाहर आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक रूप से एक साथ कार्य करना जारी रखेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय नियम–आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि करते हैं जहां देश सभी प्रकार के सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक दबावों से मुक्त हैं।

शांति और स्थिरता

हमने यूक्रेन में संघर्ष और चल रहे दुःखद मानवीय संकट पर अपनी–अपनी प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की और हिंद–प्रशांत के लिए इसके प्रभावों का आकलन किया। क्वाड नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के हमारे दृढ़ संकल्प को दोहराया। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का केन्द्रबिंदु अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान शामिल है। हमने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।

क्वाड क्षेत्र में भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। हम, आसियान एकता और केन्द्रीयता के लिए तथा इंडो–पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि करते हैं। हम, इंडो–पैसिफिक में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति पर यूरोपीय संघ की संयुक्त सूचना का स्वागत करते हैं, जिसकी घोषणा सितम्बर 2021 में की गई थी और इससे हिंद–प्रशांत क्षेत्र में यूरोपीय वचनबद्धता में वृद्धि हुई थी। हम, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) और नौवहन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता बनाए रखने के रूप में, पूर्वी और दक्षिणी समुद्र सहित नियम–आधारित समुद्री चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे। हम किसी भी प्रकार की बलपूर्वक, उत्तेजक या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं जो यथास्थिति को बदलने और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे कि विवादित सुविधाओं का सैन्यीकरण, तटरक्षक जहाजों और समुद्री मिलिशिया का खतरनाक उपयोग तथा अन्य देशों के समुद्र तट से दूर संसाधनों के दोहन को बाधित करने के प्रयास करे।

व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, हम उनके आर्थिक कल्याण में वृद्धि, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय लचीलेपन को मजबूत करने, उनकी समुद्री सुरक्षा में सुधार करने, उनके मत्स्य पालन को बनाए रखने, स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करने, शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को

कम करने और अनुकूल बनाने के लिए प्रशांत द्वीप देशों के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे, जो इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से गंभीर चुनौतियां हैं। हम प्रशांत द्वीप के भागीदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने प्रशांत द्वीप समूह फोरम की एकता और प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के लिए अपने समर्थन की फिर से पुष्टि की।

अपने बीच और अपने भागीदारों के साथ, हम संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थानों में अपने सहयोग को गहरा करेंगे, जहां बहुपक्षीय प्रणाली के लचीलेपन को सुधारने और बढ़ाने के लिए हमारी साझा प्राथमिकताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से और एक साथ, हम अपने समय की चुनौतियों का जवाब देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह क्षेत्र समावेशी, खुला और सार्वभौमिक नियमों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित है।

हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों (यूएनएससीआर) के अनुरूप कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और अपहृत जापानियों के मुद्दे के तत्काल समाधान की आवश्यकता की भी पुष्टि करते हैं। हम यूएनएससीआर के उल्लंघन में उत्तर कोरिया के अस्थिर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल विकास और लॉन्च की भी निंदा करते हैं, जिसमें कई अंतर–महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण शामिल हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान करते हैं। हम उत्तर कोरिया से यूएनएससीआर के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करने, उकसावे से दूर रहने और महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने का आग्रह करते हैं।

हम म्यांमार संकट से बहुत चिंतित हैं, जिससे गंभीर मानवीय पीड़ा हुई है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां खड़ी हुई हैं। हम म्यांमार में हिंसा को तत्काल समाप्त करने, विदेशियों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, रचनात्मक बातचीत में भागीदारी, मानवीय पहुंच और लोकतंत्र की तेजी से बहाली का आह्वान करना जारी रखते हैं। हम म्यांमार में समाधान खोजने के लिए आसियान के नेतृत्व वाले प्रयासों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं और आसियान अध्यक्ष के विशेष दूत की भूमिका का स्वागत करते हैं। हम आगे आसियान पांच सूत्रीय सहमति के तत्काल कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं।

हम सभी रूपों और घोषणाओं में स्पष्ट रूप से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की निंदा करते हैं और दोहराते हैं कि किसी भी आधार पर आतंकवादी कृत्यों का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। हम परोक्ष आतंकवाद के उपयोग की निंदा करते हैं और आतंकवादी समूहों को किसी भी सैन्य, वित्तीय या सैन्य सहायता से इनकार करने के महत्व पर जोर देते हैं जिसका उपयोग सीमा पार हमलों सहित आतंकवादी हमलों को शुरू करने या योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। हम 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों सहित आतंकवादी हमलों की अपनी निंदा दोहराते हैं। हम यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 (2021) की भी पुष्टि करते हैं, जिसमें मांग की गई है कि किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने या प्रशिक्षित करने या आतंकवादी हमलों की योजना बनाने या वित्तपोषित करने के लिए अफगान क्षेत्र का फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप, सभी देशों द्वारा धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। हम फिर से पुष्टि करते हैं कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में, हम सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे, जिसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें यूएनएससी प्रस्ताव 1267(1999) के अनुसार नामित किया गया है।

कोविड–19 और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा

दो वर्षों से अधिक समय से, दुनिया हमारे समुदायों, नागरिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रणालियों तथा अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड–19 के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रही है। क्वाड देशों ने बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के निर्माण और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने की दृष्टि से कोविड–19 प्रतिक्रिया के लिए

वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए टीके, परीक्षण, उपचार और अन्य चिकित्सा उत्पाद प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वायरस से आगे निकलने के लिए अपने सामूहिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आज तक, क्वाड साझेदारों ने सामूहिक रूप से कोवैक्स एएमसी को लगभग 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जो सरकारी दानदाताओं के कुल योगदान का लगभग 40 प्रतिशत है। हमें इंडो–पैसिफिक को कम से कम 265 मिलियन खुराक सहित 670 मिलियन से अधिक खुराक देने पर गर्व है। कोविड–19 टीकों की वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण विस्तार को ध्यान में रखते हुए, हम सुरक्षित, प्रभावी, किफायती और गुणवत्तापूर्ण–सुनिश्चित कोविड–19 टीकों को साझा करना जारी रखेंगे जहां और जब उनकी आवश्यकता होगी।

हम क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत भारत में जैविक ई–सुविधा में जेएंडजे वैक्सीन उत्पादन के विस्तार पर प्रगति का स्वागत करते हैं– टिकाऊ विनिर्माण क्षमता से कोविड–19 और भविष्य की महामारियों के खिलाफ लड़ाई में दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इस संबंध में, हम भारत में उपरोक्त टीकों के संबंध में डब्ल्यूएचओ के ईयूएल अनुमोदन के अनुदान के लिए तत्पर हैं। हम क्वाड सदस्यों के अन्य वैक्सीन से संबंधित सहयोग के साथ, क्वाड द्वारा कंबोडिया और थाईलैंड को डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित मेड इन इंडिया टीकों के दान की सराहना करते हैं जो हमारे सहयोग की स्पीष्टर उपलब्धि का एक उदाहरण है।

हम भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी खतरों से निपटना और कोविड–19 प्रतिक्रिया तथा तैयारियों को जारी रखेंगे। हम आखिरी छोर के समर्थन से प्रोत्साहन में तेजी लाएंगे, जिसमें हमारे चार देशों द्वारा विश्व स्तर पर 115 से अधिक देशों में 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक प्रदान किए गए हैं और इस सप्ताह विश्व स्वास्थ्य सभा में क्वाड–आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन अनिश्चितता को दूर करेंगे। हम ''कोविड–19 प्रायोरिटीज्ड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर एन्हांस्ड एंगेजमेंट (जीएपी)'' और कोवैक्स वैक्सीन डिलीवरी पार्टनरशिप सहित अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे। हम अमेरिका की सह–मेजबानी से सफल दूसरे ग्लोबल कोविड–19 शिखर सम्मेलन का स्वागत करते हैं, जिसमें क्वाड सदस्य शामिल हुए, जिसने वित्तीय और नीतिगत प्रतिबद्धताओं में 3.2 बिलियन डॉलर का योगदान दिया। हम इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक पुनरोद्धार के लिए समर्थन को मजबूत करेंगे।

लंबी अवधि में, हम बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के निर्माण के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संरचना और महामारी की रोकथाम, तैयारी तथा प्रतिक्रिया (पीपीआर) को मजबूत करेंगे, जिसमें वित्त और स्वास्थ्य समन्वय जैसे कि नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से और जीनोमिक निगरानी को बढ़ाकर तथा वर्तमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना शामिल है। मौजूदा क्वाड सहयोग के आधार पर, हम महामारी की क्षमता वाले नए और उभरते रोगाणुओं की जल्द पहचान करने तथा निगरानी में सुधार करने की अपनी क्षमता को बढ़ाएंगे तथा महामारी और महामारी के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। संक्रामक रोगों की रोकथाम और रोकथाम रोधी नए टीकों के विकास के लिए, क्वाड पार्टनर्स ने सीईपीआई के काम के अगले चरण के लिए सामूहिक रूप से 524 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जो कुल सार्वजनिक निवेशकों का

लगभग 50 प्रतिशत है।

हम यूएचसी के दोस्तों के समूह के सदस्यों के रूप में, 2023 में होने वाली यूएचसी पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक की अगुवाई में पीपीआर को बढ़ाने और यूएचसी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला को और मजबूत करने और सुधारने के लिए वैश्विक नेतृत्व लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आधारभूत संरचना

हमने बुनियादी ढांचे पर सहयोग को गहरा करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम ऋण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रतिबद्धता भी साझा करते हैं, जो कई देशों में महामारी से बढ़ गए हैं।

क्वाड साझेदार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचा प्रदान करने में तेजी

लाने के लिए दशकों के कौशल और अनुभव को एक साथ लाए हैं। हम कमियों को पाटने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भागीदारों तथा क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, क्वाड अगले पांच वर्षों में इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में 50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की सहायता और निवेश का विस्तार करने की कोशिश करेगा।

हम जी20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण के मुद्दों से निपटने के लिए और ''क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल'' सहित संबंधित देशों के वित्त अधिकारियों के साथ निकट सहयोग में ऋण स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए देशों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काम करेंगे जिसमें अनेक बहुपक्षीय और बहुपक्षीय क्षमता निर्माण सहायता शामिल है।

हम क्वाड नेताओं की बैठक के अतिरिक्त चार देशों के विकास वित्त संस्थानों और एजेंसियों की बैठक का भी स्वागत करते हैं। हम हिंद–प्रशांत को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए अपने टूलकिट और विशेषज्ञता को जोड़ने के लिए विशेषज्ञों, अपने क्षेत्र और एक–दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

हम क्षेत्रीय और डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा से संबंधित सुविधाओं में आपदा लचीलापन सहित जलवायु लचीलापन जैसे पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे तथा पूरक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जो क्षेत्र में निरन्तर और समावेशी विकास में योगदान करने के लिए इंडो–पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण सहित क्षेत्र की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

जलवायु

नवीनतम आईपीसीसी रिपोर्टों में जोर दिए गए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम दृढ़ता से पेरिस समझौते को लागू करेंगे और सीओपी26 के परिणामों को पूरा करेंगे, वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के हमारे प्रयासों में तेजी लाएंगे, जिसमें इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों तक पहुंचना शामिल है और क्षेत्र में भागीदारों द्वारा जलवायु कार्यों का समर्थन, सुदृढ़ीकरण तथा वृद्धि करना, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों, जलवायु पूंजी जुटाना तथा नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और तैनाती को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

आज, हम दो विषयों के रूप में ''शमन'' और ''संयोजन'' के साथ ''क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (क्यू–चैम्प)'' लॉन्च करते हैं। क्यू–चैम्प में क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप के तहत चल रही गतिविधियां शामिल हैः हरित नौवहन और बंदरगाह जिनका उद्देश्य प्रत्येक क्वाड देश के इनपुट पर एक साझा ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण का लक्ष्य; प्राकृतिक गैस क्षेत्र से स्वच्छ हाइड्रोजन और मीथेन उत्सर्जन में स्वच्छ ऊर्जा सहयोग; सिडनी एनर्जी फोरम के योगदान का स्वागत करते हुए स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना; प्रशांत द्वीप देशों के साथ एक कार्य रणनीति विकसित करने के लिए जलवायु सूचना सेवाएं; और आपदा एवं जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे जैसे आपदा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के गठबंधन के माध्यम से प्रयास सहित आपदा जोखिम में कमी शामिल है। इसमें स्वच्छ ईंधन अमोनिया, सीसीयूएस/कार्बन पुनर्चक्रण, सहयोग और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत उच्च सम्पूर्णता वाले कार्बन बाजारों को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण समर्थन, जलवायु दृ स्मार्ट कृषि, सबनेशनल जलवायु कार्यों और इकोसिस्टम आधारित संयोजन शामिल हैं। क्यू–चैम्प को स्पपष्ट बनाने के लिए, हम अपने चार देशों के साथ–साथ इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु कार्यों के समर्थन में अपने कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रशांत के द्वीप राष्ट्रों के लिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न भारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं।

हम जलवायु परिवर्तन पर मजबूत कार्रवाई के लिए नई ऑस्ट्रेलियाई सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं, जिसमें 2050 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए कानून बनाना और राष्ट्रीय स्तर पर एक नया, महत्वाकांक्षी निर्धारित योगदान दर्ज करना शामिल है।

साइबर सुरक्षा

जटिल साइबर खतरों के साथ तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में हम साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं। एक स्वतंत्र और खुले इंडो–पैसिफिक के लिए क्वाड नेताओं की परिकल्पना को पूरा करने के लिए, हम डिजिटल रूप से सक्षम उत्पादों और सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला में संभावित जोखिमों की पहचान और संभावित खतरों का मूल्यांकन करके अपने राष्ट्रों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा में सुधार करने और सरकारी खरीद के लिए आधारभूत सॉफ्टवेयर सुरक्षा मानकों को जोड़कर, व्यापक सॉफ्टवेयर विकास इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारी सामूहिक क्रय शक्ति का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि सभी उपयोगकर्ता लाभान्वित हो सकें। क्वाड साझेदार क्वाड साइबर सुरक्षा साझेदारी के अंतर्गत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे और हमारे देशों में व्यक्तिगत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की मदद करने के लिए इंडो–पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे की बेहतर सुरक्षा के लिए पहले क्वाड साइबर सुरक्षा दिवस की शुरुआत करेंगे ताकि खुद को साइबर खतरों से बचा सकें।

महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां

क्वाड क्षेत्र की समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के दोहन पर केंद्रित है। 5जी के क्षेत्र में और 5जी से परे, दूरसंचार आपूर्तिकर्ता विविधता पर प्राग प्रस्तावों का स्वागत करते हुए, हम 5जी आपूर्तिकर्ता विविधीकरण और ओपन आरएएन पर सहयोग के एक नए ज्ञापन पर हस्ताक्षर

के माध्यम से पारस्परिकता और सुरक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हम उद्योग के साथ अपने जुड़ाव को भी गहरा कर रहे हैं, जिसमें ओपन आरएएन ट्रैक 1.5 इवेंट शामिल हैं और इस क्षेत्र में खुली तथा सुरक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की तैनाती पर सहयोग करने के तरीके तलाश रहे हैं।

हमने वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्वाड की क्षमता और कमजोरियों का मानचित्रण किया है और सेमीकंडक्टूरों के लिए एक विविध और प्रतिस्पर्धी बाजार का एहसास करने के लिए अपनी पूरक शक्तियों का बेहतर लाभ उठाने का निर्णय लिया है। इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर शुरू किया गया महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला पर सिद्धांतों का सामान्य विवरण, सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर हमारे सहयोग को आगे बढ़ाता है, इस क्षेत्र में विभिन्न जोखिमों के खिलाफ हमारे लचीलेपन को बढ़ाने के लिए एक सहकारी आधार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठनों में हमारे सहयोग, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो ने बहुत प्रगति की है और हम नए अंतर्राष्ट्रीय मानक सहयोग नेटवर्क (आईएससीएन) के माध्यम से इस तरह के सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद करते हैं। इस सहयोग से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों द्वारा निर्देशित है। हम मानचित्रण और संबंधित ट्रैक 1.5 तथा क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर भविष्य के फोकस पर अपने प्रयासों के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी में गहन चर्चा के बाद हम अपने क्षितिज स्कैनिंग सहयोग को मजबूत करना जारी रखते हैं। हम महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पूंजी का विस्तार करने के लिए उद्योग भागीदारों के साथ नेटवर्किंग के लिए एक व्यापार और निवेश फोरम बनाएंगे।

क्वाड फेलोशिप

क्वाड फेलोशिप के आधिकारिक लॉन्च का स्वागत करते हैं, जो अब आवेदन के लिए खुला है। क्वाड फेलोशिप एसटीईएम क्षेत्रों में स्नातक डिग्री हासिल करने के लिए हमारे देशों के 100 छात्रों को हर साल अमेरिका लाएगा और श्मिट फ्यूचर्स द्वारा व्यवस्थित है। क्वाड फेलो की पहली कक्षा 2023 की तीसरी तिमाही में शुरू होगी और हम अगली पीढ़ी के एसटीईएम दिमागों के एक प्रतिभाशाली समूह का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं जो हमारे देशों का अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार में नेतृत्व करेंगे।

अंतरिक्ष

अंतरिक्ष से संबंधित अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकियां जलवायु परिवर्तन, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तथा महासागरों और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने में भी योगदान दे सकती हैं। प्रत्येक क्वाड पार्टनर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डेटा और अनुप्रयोगों के लिए सार्वजनिक पहुंच में सुधार करने का प्रयास करेगा। हम एक पृथ्वी अवलोकन–आधारित निगरानी और स्थिर विकास ढांचा बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम एक ''क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल'' प्रदान करने के साथ–साथ अंतरिक्ष–आधारित नागरिक पृथ्वी अवलोकन डेटा साझा करने का प्रयास करेंगे, जो हमारे संबंधित राष्ट्रीय उपग्रह डेटा संसाधनों के लिंक को एकत्रित करता है। हम पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र सहित अंतरिक्ष एप्लीकेशनों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे और क्षेत्र के देशों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें अप्रत्याशित घटनाओं का जवाब देने के लिए अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग करने पर भागीदारी शामिल है। हम अंतरिक्ष के निरन्तर उपयोग के लिए नियमों, मानदंडों, दिशानिर्देशों और सिद्धांतों पर भी परामर्श करेंगे और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग (सीओपीयूओएस) दिशानिर्देशों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के संबंध में संयुक्त कार्यशालाओं के माध्यम से क्षेत्र के देशों के लिए सहायता का विस्तार करेंगे।

समुद्री क्षेत्र में जागरूकता और एचएडीआर

हम समुद्री क्षेत्र में एक नई जागरूकता पहल, इंडो–पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (आईपीएमडीए) का स्वागत करते हैं, जिसे मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने और गैर–कानूनी तरीके से मछली पकड़ने का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया है। आईपीएमडीए हमारे समुद्रों में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत, साझा समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करके हिंद–प्रशांत देशों और हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया तथा प्रशांत द्वीपों में क्षेत्रीय सूचना फ्यूजन केंद्रों के परामर्श से सहायता और काम करेगा। आईपीएमडीए में क्वाड का अर्थ हैः ठोस परिणामों की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों को उत्प्रेरित करना जो इस क्षेत्र को अधिक स्थिर और समृद्ध बनाने में मदद करता है। 3 मार्च 2022 को हमारी वर्चुअल मीटिंग के बाद अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए, हम आज "इंडो–पैसिफिक में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर क्वाड साझेदारी (एचएडीआर) की स्थापना की घोषणा करते हैं। यह साझेदारी क्षेत्र में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारे सहयोग को और मजबूत करेगी।

एक स्वतंत्र और खुले इंडो–पैसिफिक के लिए एक साझा दृष्टिकोण के साथ, हम एक बार फिर मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों के महत्व पर जोर देते हैं और इस क्षेत्र में ठोस परिणाम देने के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा करते हुए, हम क्वाड गतिविधियों को नियमित करेंगे, जिसमें नेताओं और विदेश मंत्रियों की नियमित बैठकें शामिल हैं। हम ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित 2023 में अपना अगला व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए सहमत हैं।

वसुंधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को साकार करते यह सम्मेलन सार्थक रहा।

महिला सशक्तिकरण

की पर्याय 'मोदी सरकार'

मीना चौबे

2014 में केन्द्र की सत्ता में जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आये हैं महिलाओ को बराबरी का दर्जा देने व उनको आत्म सम्मान से जीवन देने के लिए वो सदा तत्पर रहते है।उसमें भी खास कर जरूरत मंद ज्यादातर महिलाओ के हिस्से में संसाधनों की वाजिव भागीदारी का हक नही मिल सका ऐसी आधी आबादी के उन्नयन उनकी प्राथमिकताओं में लगातार रहा है जैसे ही केंद्र में 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में आते है। उनके चिंतन में प्रथम दृष्टया आधी आबादी की वेदना पीड़ा समाप्त करने के लिए देश भर में करोड़ो इज्जतघर (शौचालय)से महिलाओ की समस्यायों से मुक्ति दिलाने का सफल बीणा उठाते हैं।

ऐसे ही जनधन के माध्यम से करोड़ो महिलाओ के अपने खूंटे के पैसे को बैकिंग व्यवस्था में साथ जोड़ने का सुअवसर प्रदान कर सुरक्षित करने का आह्वान कर स्त्रीधन को सुरक्षा देने का कार्य किया।

डिजिटल इंडिया द्वारा महिलाओ को एक अनंत शक्ति प्रदान कर महिलाओ को सीधे उनके खाते में लाभ प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराने का एक भरोसा एक विश्वास पैदा करने का कार्य किया।

महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अंब्रेला योजना मिशन शक्ति के तहत केन्द्र सरकार ने शुरू की। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हर संकट में साथ देने वाली योजनाओं के साथ जीवन आसान करने वाली योजनाएं भी केंद्र सरकार की महिलाओं के प्रति सार्थक और समर्पित सोच को प्रदर्शित कर रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मुद्रा योजना के मदद से महिलाओं के सशक्त करने में सूक्ष्म और लघु उद्योग इकाइयों को विनिर्माण व्यापार या सेवा में सृजन की गतिविधि के लिए पीएम मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी में ₹50000 तक के किशोर श्रेणी ₹500000 तक और तरुण से इन्हें ₹500000 से ₹1000000 तक लोन देने वाली योजना की सबसे अधिक लाभार्थी महिलाएं ही हैं। महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्टअप जिसका उद्देश्य महिला सूक्ष्म उद्योग के लिए पोषण एवं वृद्धि का संचालन करने से देश में महिला उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम में बहुत तेजी से

सुधार हो रहा है महिलाओं के नेतृत्व वाले ढांचे उद्यमों के ढांचे की स्थिति में सुधार के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिला द्वारा स्टार्टअप से महिलाएं सक्षम व मजबूत हो रही हैं। केन्द्र की एक योजना मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण की मिशाल बन महिलाओं तक योजनाओं की पहुंच व अंतिम छोर तक ट्रैकिंग महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा और सशक्तीकरण साथ मजबूत कर महिलाओं के जीवन चक्र की निरंतरता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर मंत्रालय विभाग और शासन के विभिन्न स्तरों पर मेल कराने के साथ अधिक से अधिक जनभागीदारी पंचायत व स्थानीय शासन की सहायता से महिला नेतृत्व वाले विकास के सरकार की दृष्टिकोण को आगे रखकर मिशन शक्ति, एक अंब्रेला स्कीम शुरू की गई है। जो बेहद प्रभावी हो मिशन शक्ति के दो योजना है जिसमें संभाल और सामर्थ्य सम्भाल में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा की योजना वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन बेटी बचाओ और नारी अदालत को

जोड़ रखा गया है। जबकि सामर्थ में उज्ज्वला स्वाधार कामकाजी महिलाओं के छात्रावास सहित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शामिल की जा चुकी है जिससे महिलाए स्वयं को सक्षम व सबल महसूस कर रही। मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का नया आधार 1 मई 2016 से शुरू हुई उज्जवला 1.0 उज्वाला 2.0 में 12 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन देकर महिलाओं की रसोई से धुआं मुक्त महिलाओं के स्वास्थ्य सकारात्मक जीवन देने का कार्य हुआ है। 56 साल से अधिक पुराने कानून में बदलाव के साथ मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला आवेदकों के लिए प्राथमिकता तय की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आयुश्मान योजना के माध्यम से इलाज के आभाव में दबी कुचली 47 फीसदी आधी आबादी स्वयं को स्वस्थ्य रख पा रही है। आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे पुलिस सुविधा कानूनी सहायता परामर्श चिकित्सा सहायता सुगमता से उपलब्ध कराने का कार्य मोदी सरकार द्वारा हो रहा है। इस तरह देश भर के 729 जिलों के लिए 733 सेंटर को मंजूरी दी गई है जिसमें 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 704 सेंटर लागू किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में 493 लाख महिलाओं को सहायता प्राप्त कर अपनी जीवन को खुशहाल बना पा रही है। इसी तरह केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधार गृह योजना द्वारा में कठिनाई में फंसी महिलाओं को पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार में कृष्ण कुटीर गृह का निर्माण उत्तर प्रदेश के वृंदावन में किया गया। इसकी शुरुआत 31 अगस्त 2018 को की गई जो देश में विधवाओं के लिए सबसे बड़ा आश्रय गृह है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले 5 वर्षों में जितनी मदद की गई उससे लगभग 15 गुना बढ़ोतरी कर आधी आबादी के जीवन को सहज बनाने का कार्य हुआ है ।

महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले 1000000 रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था अब यह सीमा दोगुनी कर दी गयी है, जिससे महिलाओं को निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में गतिशीलता बनी रहे। 2.5 करोड़ से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते अभी तक खोले जा चुके हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित वर्षा वन में 1 का 10 फ़ीसदी यानी 1000 करोड रुपए महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप के लिए आरक्षित कर उन्हें मजबूती प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए क्षमता विकास का कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर भी महिला उद्यमियों को समर्पित है। 8 दिसंबर 2021 तक जो 7000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है उसमें 46 फ़ीसदी यानी कि 27665 में कम से कम एक महिला को निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है।इसमें प्रति बैंक शाखा कम से कम 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एक महिला को 10 लाख से एक करोड़ के बीच में लोन उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला शक्ति केंद्र नवंबर 2017 से चलाए जा रहे हैं इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुरू होने से लिंगानुपात में सुधार के साथ–साथ बेटियां अब देश की शान बन रही है घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए शुरू की गई योजना का सुखद आधार भी कई राज्यों के सामने आए हैं। नवंबर 2021 में जारी नेशनल फैमिली सर्वे के अनुसार देश में पहली बार एक हजार पुरुषों के मुकाबले

महिलाएं 1020 है। आधी आबादी के लिए प्रसव के दौरान मां और बच्चे का ख्याल रखने के लिए सरकार ने सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत किया गया जिससे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत अस्पतालों और ट्रेंड नर्सों की निगरानी के बीच महिलाओं का प्रसव सुनिश्चितता के साथ हो सके तथा महिला और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके।यह योजना 10 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई इसके तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बिना किसी फीस के सरकारी सुविधाओ के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रही है। ऐसे ही जिन महिलाओं की रुचि सिलाई–कढ़ाई में रही है और इस टैलेंट को प्रोफेशन में तब्दील करना चाहती हैं, उनके लिए यह योजना बहुत लाभदायक है। 20 साल से 40 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है ।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्त्री भ्रूण हत्या में आ रही गिरावट लगभग समाप्ति की ओर है। साथ ही, बच्चियां पढ़ाई कर स्वयं को महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उन महिलाओं की मदद करती है, जो घरेलू या किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को यह सुविधा दी गई है कि मदद के समय वे कभी भी पुलिस, कानून और चिकित्सा जैसी सुविधाएं ले सकती हैं। इसके लिए बस टोल फ्री नंबर 181 पर फोन करना होता है।

जहां तक महिला सशक्तिकरण नए भारत में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन करने का माहौल नियमों में बदलाव और नई योजनाओं से बनाया है भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट कमांडो केंद्रीय पुलिस बल में भर्ती शुरू कराई गई सैनिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी देने के अनुकूल प्रावधान बनाया गया।

समर्थ योजना मोदी सरकार के सामर्थ्य योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को अलग–अलग प्रकार के वस्त्र उत्पादन के गुण और उससे जुड़े कार्यों के बारे में सिखाया जा रहा है इसकी मदद से महिलाएं वस्त्र उद्योग में जान फूंक इससे न केवल ग्लोबल टैक्सटाइल बिजनेस में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है बल्कि इसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना इस योजना की शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को की गई थी यह स्कीम 10 साल के से कम उम्र के बच्चों को उच्च शिक्षा देने और उसकी शादी कराने के लिए शुरू की गई थी इसके तहत बच्चियों का सुरक्षित भविष्य निश्चित कराया जाता है किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर परिजन अपनी 10 साल की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। महिलाओं के लिए यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। महिलाएं इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर पा रही है। इन योजनाओं के कारण महिलाएं केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनती बल्कि, सभी क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य कर सफलता प्राप्त कर रही है और अपने तथा अपने परिवार के जीवन को सुखद बना रही है। केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के विकास के लिए नई –नई योजनाएं लागू करते हैं और महिलाएं इन योजनाओं के अनुसार कार्य करके अपने जीवन को खुशहाल बनाती हैं तथा इन योजनाओं की वजह से

महिलाओं के जीवन में बहुत से बदलाव देखने को भी मिल रहा हैं। वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपनी भूमिका का प्रदर्शन ना किया हो, सरकार ने 2022 में गरीबों को सहायता प्रदान करने और उन्हें लाभ देने के लिए गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन बोनस के रूप में प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से हर गृहणी को अपने बच्चों व परिवार को भूखे पेट नही सोना पड़ा रहा है। इससे कोरोना काल से लेकर अब तक देश के सभी गरीब नागरिको को राहत मिल रही है।

अतः हम आधी आबादी कह सकती है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार का सेवा सशासन व गरीब कल्याण महिला सशक्तिकरण की पर्याय है।

गरीब कल्याण योजना लेकर घर-घर जायेंगे कार्यकर्ता : गोविन्द

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल व अमरपाल मौर्य ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्ल ने कहा कि 2014 में, भारत के लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए में अपना विश्वास व्यक्त किया है। 30 वर्षों के बाद भारत के लोंगों ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर अपना आशीर्वाद दिया। 2019 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और भी बड़े जनादेश के साथ सरकार में लौटी और भाजपा की सीटों की संख्या 282 से बढकर 303 हो गई। किसी प्रधानमंत्री का अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद, उन्हीं के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार की वापसी होना करीब 6 दशकों के बाद हुआ है।

2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी ने पदभार ग्रहण किया, तो उन्हें पहले दिन से ही भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 का चुनावी जनादेश यूपीए सरकार के पॉलिसी, पैरालिसिस, भ्रष्टाचार और जबरदस्त वंशवादी राजनीति के बाद था। 135 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य और कौशल से संचालित और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र पर चलने वाली मोदी सरकार ने गरीबी दूर करने और देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कई पहल की हैं। मोदी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 'अंत्योदय' के मंत्र के अनुरूप काम कर रही है, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना। श्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि एक कुशल नेतृत्व क्या होता है।

7 अक्टूबर 2021 को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 12.5 साल और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 7.5 साल) पूरे किये। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति में यह एक विशिष्ट उपलब्धि है जिसे कुछ ही लोगों ने हासिल किया है। दूसरों की सेवा करने और अपने साथी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उनके निरन्तर प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है।

श्री शुक्ल ने कहा कि हमें राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता पर गर्व महसूस होता है। जब हम भारतीय के जीवन को बदलते हुए देखते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र को सशक्त बना रही है और समृद्धि की नई ऊंचाईयों की ओर ले जा रही है।

उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद से 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक सरकार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, वह भी दो–तिहाई बहुमत से। साथ ही पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार वापसी की है। प्रदेश के 19 जिलों में भाजपा को छोड़ बाकी सभी पार्टियों का खाता भी नहीं खुला। यूपी में पहली बार लगातार चार चुनाव–2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और अब 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को प्रदेश की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा का वोट शेयर भी 39 प्रतिशत से बढ़ कर 42 प्रतिशत हुआ है। समाज के सभी वर्गों का पूरा सहयोग भाजपा को मिला है।

शुक्ल ने आगामी 30 मई को केंद्र सरकार के आठ वर्ष

पूरे होने पर पार्टी द्वारा 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रम होंगे। टू नेशन कार्यक्रम 1 या 2 जून को प्रदेश मुख्यालय में किया जाएगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर प्रेस कान्फ्रेस कर केंद्र सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन जिलाप्रभारी, जिलाध्यक्ष, सांसद के द्वारा किया जाएगा। साथ ही सरकार के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार के चयनित लाभार्थी (10 योजनाओं के) उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, गरीब कल्याण योजना, घर–घर नल योजना के लाभार्थी को कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

यूपी में पहली बार लगातार चार चुनाव-2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और अब 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में भाजपा को प्रदेश की जनता ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया है।

उन्होंने बताया कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 08 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु 75 घंटे बूथ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, एमएलसी, अन्य जन प्रतिनिधि, प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मण्डल के सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक दिन 08 घंटे तक किसी एक बूथ पर जाकर बूथ आधारित गतिविधियों में सहभागिता करेगें।

30 मई को केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर पार्टी द्वारा 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रम होंगे।

कार्यक्रम के तहत बूथ के कार्यकर्ता घर–घर सम्पर्क करना एवं केन्द्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जन–जन तक पहुंचाएगें। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं द्वारा प्रभात फेरी निकालना व शहीद परिवार के घर जाकर उनका सम्मान भी किया जाएगा। केन्द्र व राज्य सरकार की भाजपा सरकार लाभार्थीयों के घर जाकर उन्हे पौधा भेंट कर वृक्षारोपण करवाने के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएगें।

नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर सेवा व सुशासन और गरीब कल्याण के नाम पर 75 घंटे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की भी योजना तय की गई है। जिसके तहत पहले दिन विधानसभा स्तर पर वृक्षारोपण व तलाब सफाई के कार्यक्रम किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किया जाएगा। दूसरे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/आंगनवाडी पर स्वास्थ परीक्षण शिविर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। जबकि तीसरे दिन विधानसभा स्तर पर महापुरूषों की मूर्ति पर माल्यार्पण व बस्ती में स्वच्छता अभियान अनुसूचित मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा। चौथे दिन जनपद स्तर पर महापुरूषों पर माल्यार्पण व बस्ती में स्वच्छता अभियान अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा। पांचवे दिन विधानसभा स्तर पर प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर स्वच्छता व वृक्षारोपण का अभियान पिछडा मोर्चा चलाएगा।

छठे दिन समाज के कमजोर वर्ग के लिए सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण का कार्य भाजपा संगठन चलाएगा। जबकि सातवें दिन शहरी गरीबों के लिए वार्ड पर स्वास्थ परीक्षण शिविर, स्वच्छता अभियान स्थानीय निकाय टीम चलाएगी। आठवें दिन – जनपद स्तर पर विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां आर्जित करने वाले लोंगो का सम्मान समारोह भाजपा संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा। जबकि नौवें दिन टीकाकरण की सुविधा और स्वास्थ्य सेवकों का सम्मान समारोह चिकित्सा प्रकोश्ठ द्वारा किया जाएगा। अभियान के आखिरी दिन केन्द व राज्य की भाजपा सरकार के लाभार्थियों के घरों पर बूथ स्तर पर सम्पर्क करेगी व अन्य कार्यक्रम पार्टी आयोजित करेगी।

श्री शुक्ल ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 01 जून से 13 जून 2022 के मध्य जिला केंद्रो पर गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल होंगे। जिला स्तर पर होने वाली जनसभा को केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश सरकार के मंत्रीगण व पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेता सम्बोधित करेंगे।

मन्दिर अब बनने लगा है...

श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री एवं विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपतराय जी तथा श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र द्वारा दी गई निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रगति की 23 मई, 2022 तक के स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि–

मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) मंदिर और परकोटा (प्राचीर) के निर्माण के लिए ठेकेदार नियुक्त हैं। टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स (टीसीई) परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त हैं। और चार इंजीनियर हैं श्री जगदीश आफले पुणे आईआईटी–मुंबई, गिरीश सहस्त्रभुजनी गोवा आईआईटी–मुंबई, जगन्नाथजी औरंगाबाद, अविनाश संगमनेरकर नागपुर ये सभी ट्रस्ट की ओर से स्वयंप्रेरणा स्वेच्छा से सेवा दे रहे हैं।

05 अगस्त, 2020 को, भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के मंदिर के गर्भगृह (गर्भगृह) स्थल पर पूजा करके निर्माण कार्य को गति प्रदान की थी।

एल एंड टी ने भविष्य के मंदिर की नींव के लिए एक डिजाइन का प्रारूप बनाया था, उसके अनुरूप परीक्षण किया गया था, परंतु आशानुरूप परिणाम नहीं आए तो इस विचार को स्थगित कर दिया गया, यह परीक्षण अगस्त–सितंबर–अक्टूबर, 2020 में किया गया था।

नवंबर–2020 के महीने में, निदेशक (सेवानिवृत्त) – आईआईटी – दिल्ली की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वर्तमान) – आईआईटी – गुवाहाटी, निदेशक (वर्तमान) – एनआईटी – सूरत, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के आईआईटी के प्रोफेसर, निदेशक–सीबीआरआई–रुड़की, एलएंडटी और टीसीई की ओर से वरिष्ठ इंजीनियर थे , निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र की प्रेरणा से यह विशेषज्ञ समिति बनी थी।

जीपीआर सर्वेक्षण – नवंबर–2020 के महीने में, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई)–हैदराबाद से अनुरोध किया गया था कि वह निर्माण स्थल पर जमीन का अध्ययन करके और अपनी रिपोर्ट प्रदान करे ताकि नींव के डिजाइन को तय करने में मदद हो सके। एनजीआरआई ने जीपीआर तकनीक का उपयोग करते हुए भू–सर्वेक्षण किया और क्षेत्र की खुली खुदाई करके भूमि के नीचे का मलबा और ढीली मिट्टी को हटाने का सुझाव दिया। यह जीपीआर सर्वेक्षण नवंबर–दिसंबर 2020 में आयोजित किया गया था।

उत्खनन – निर्धारित मंदिर स्थल और उसके आसपास लगभग छह एकड़ भूमि से लगभग 1.85 लाख घन मीटर मलबा और पुरानी ढीली मिट्टी को हटाया गया। इस काम में करीब 3 महीने (जनवरी–फरवरी–मार्च, 2021) लगे। यह स्थल एक विशाल खुली खदान की तरह दिखता था – गर्भगृह में 14 मीटर की गहराई और उसके चारों ओर 12 मीटर की गहराई वाला मलबा व बालू हटाई गई। एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया।

बैक–फिलिंग और मिट्टी को सुदृढ़ करने के लिए रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट (आरसीसी) का उपयोग – चेन्नई आईआईटी के प्रोफेसरों ने इस विशाल गड्ढे को भरने के लिए विशेष इंजीनियरिंग मिश्रण का सुझाव दिया। आरसीसी कंक्रीट को सुझाई गई विधि परत दर परत के रूप में कंक्रीट डालना था। 12 इंच की एक परत को 10 टन भारी क्षमता वाले रोलर द्वारा 10

इंच तक दबाया जाता था। घनत्व मापा जाता था। गर्भगृह में 56 परत और शेष क्षेत्र में 48 परतों को डाला गया। इसे पूरा होने में अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक लगभग 6 महीने लगे । उक्त फिलिंग को 'मिट्टी सुदृढ़ीकरण द्वारा भूमि सुधार' नाम दिया गया।

मानव निर्मित चट्टान – यह कहा जा सकता है कि मिट्टी के भीतर एक विशाल मानव निर्मित चट्टान,कम से कम 1,000 वर्षों के लिए दीर्घायु और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई है।

अक्टूबर 2021 – जनवरी 2022 के मध्य भूमिगत RCC की ऊपरी सतह पर, और अधिक उच्च भार वहन क्षमता की एक और 1.5 मीटर मोटी सेल्फ–कॉम्पैक्टेड कंक्रीट RAFT (लगभग 9,000 क्यूबिक मीटर मात्रा में) को 9डजतग 9डजत के आकार के खंडों में बैचिंग प्लांट, बूम प्लेसर मशीन और मिक्सर का उपयोग करके डाला गया था। RAFT के निर्दोष निर्माण के इस चरण में IIT–कानपुर के एक प्रोफेसर और परमाणु रिएक्टर से जुड़े एक वरिष्ठ इंजीनियर ने भी योगदान दिया।

हम कह सकते हैं कि RCC और RAFT दोनों संयुक्त रूप से, भविष्य के मंदिर सुपर–स्ट्रक्चर की नींव के रूप में कार्य करेंगे। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों और संगठनों के सामूहिक विमर्श का यह परिणाम है। इस त।थ्ज को पूरा होने में चार महीने लगे (Oct-21-Jan-2022)

प्लिंथ कार्य – मंदिर के फर्श / कुर्सी को ऊंचा करने का कार्य 24 जनवरी 22 , को शुरू हुआ और यह अभी भी प्रगति पर है। प्लिंथ को RAFT की ऊपरी सतह के ऊपर 6.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाएगा। प्लिंथ को ऊंचा करने के लिए कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ब्लॉक की लंबाई 5 फीट, चौड़ाई 2.5 फीट और ऊंचाई 3 फीट है। इस कार्य में लगभग 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉकों का उपयोग किया जाएगा। सितंबर, 2022 के अंत तक प्लिंथ को ऊंचा करने का काम पूरा होने की अपेक्षा है।

बहुत शीघ्र गर्भगृह और उसके आसपास नक्काशीदार बलुआ पत्थरों को रखना प्रारम्भ होगा। प्लिंथ का काम और नक्काशीदार पत्थरों की स्थापना एक साथ जारी रहेगी। राजस्थान के भरतपुर जिले में बंसी–पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों से गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। मंदिर में करीब 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान में सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे में नक्काशी स्थल से नक्काशीदार पत्थर अयोध्या पहुंचने लगे हैं।

मंदिर के गर्भगृह क्षेत्र के अंदर राजस्थान की मकराना पहाड़ियों के सफेद संगमरमर का प्रयोग किया जाएगा। मकराना संगमरमर की नक्काशी का कार्य प्रगति पर है और इनमें से कुछ नक्काशीदार संगमरमर के ब्लॉक भी अयोध्या पहुंचने लगे हैं।

परकोटा–आच्छादित बाहरी परिक्रमा मार्ग–मंदिर निर्माण क्षेत्र और उसके प्रांगण के क्षेत्र सहित कुल 8 एकड़ भूमि को घेरते हुए एक आयताकार दो मंजिला परिक्रमा मार्ग परकोटा बनेगा, इसी के पूर्व भाग में प्रवेश द्वार होगा। इसे भी बलुआ पत्थर से बनाया जाएगा। यह परकोटा भीतरी भूतल से 18 फीट ऊंचा है और चौड़ाई में 14 फीट होगा। इस परकोटा में भी 8 से 9 लाख घन फीट पत्थर का उपयोग होगा।

कुल पत्थर की मात्रा– इस मंदिर परियोजना में – परकोटा (नक्काशीदार बलुआ पत्थर) के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थरों की मात्रा लगभग 8 से 9 लाख क्यूबिक फीट है, 6.37 लाख घन फीट बिना नक्काशी वाला ग्रेनाइट प्लिंथ के लिए, लगभग 4.70 लाख क्यूबिक फीट नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर मंदिर के लिए, 13,300 घन फीट मकराना सफेद नक्काशीदार संगमरमर गर्भगृह निर्माण के लिए और 95,300 वर्ग फुट फर्श और क्लैडिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा।

रिटेनिंग वॉल – मंदिर के चारों ओर मिट्टी के कटान को रोकने और भविष्य में संभावित सरयू बाढ़ से बचाने के लिए दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में रिटेनिंग वॉल का निर्माण भी चल रहा है। सबसे निचले तल पर इस वॉल की चौड़ाई 12 मीटर है और नीचे से इस वॉल की कुल ऊंचाई लगभग 14 मीटर होगी। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मंदिर के पूर्व से पश्चिम की ओर के स्तरों में 10 मीटर का अंतर है अर्थात पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर ढलान है।

वर्तमान में सभी गतिविधियां एक साथ प्रगति पर हैं, उदाहरण के लिए, गर्भगृह के चारों ओर प्लिंथ और नक्काशीदार गुलाबी बलुआ पत्थर के ब्लॉकों की स्थापना, पिंडवाड़ा में गुलाबी बलुआ पत्थरों की नक्काशी, मकराना मार्बल्स की नक्काशी और आरसीसी रिटेनिंग वॉल निर्माण आदि। मंदिर का यह निर्माण कार्य निश्चित ही एक इंजीनियरिंग चमत्कार कहा जायेगा।

प्रथम चरण में एक तीर्थ सुविधा केंद्र लगभग 25,000 तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। इसे पूर्व की दिशा में मंदिर पहुंच मार्ग के निकट बनाया जाएगा।

भगवान वाल्मीकि, केवट, माता शबरी, जटायु, माता सीता, विघ्नेश्वर (गणेश) और शेषावतार (लक्ष्मण) के मंदिर भी योजना में हैं और इन्हें कुल 70 एकड़ क्षेत्र के भीतर परन्तु परकोटा के बाहर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में निर्माण किया जायेगा।

मंदिर के आयामः

(i) भूतल पर पूर्व–पश्चिम दिशा में लंबाई – 380 फीट।

(ii) भूतल पर उत्तर–दक्षिण दिशा में चौड़ाई – 250 फीट।

(iii) गर्भगृह पर जमीन से शिखर की ऊंचाई – 161 फीट।

(iv) बलुआ पत्थर के स्तंभ– भूतल–166; प्रथम तल –144; दूसरा तल – 82 (कुल–392)

आम तौर पर हर महीने निर्माण समिति सभी इंजीनियरों और वास्तुकारों के साथ श्री नृपेंद्र मिश्राजी की अध्यक्षता में 2 से 3 दिनों तक बैठती है और प्रत्येक विवरण पर बहुत बारीकी से चर्चा करती है। श्री सी.बी. सोमपुरा, अहमदाबाद मंदिर और परकोटा के वास्तुकार हैं, जबकि श्री जय काकतीकर (डिजाइन एसोसिएट्स, नोएडा) परकोटा से बाहर के शेष क्षेत्र के लिए वास्तुकार हैं।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण समग्र, परोपकारी और समकालिक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। यह देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगा। आने वाली पीढ़ियां इसे सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए अग्रणी कार्य के रूप में देखेंगी।

युवा शिविर वडोदरा

नया भारत, नई सोंच, पुरानी संस्कृति दोनों को साथ लेकर युवा पीढ़ी मानव जाति को दिशा दें: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री स्वामीनारायण मंदिर, कुलधाम और करेलीबाग, वडोदरा स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर ने युवा शिविर उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रंथ हमें सीख देते हैं कि हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र–निर्माण करना ही हर समाज की बुनियाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का जो शिविर आज चलाया जा रहा है, वह न केवल हमारे युवाओं में अच्छे 'संस्कार' पैदा कर रहा है, बल्कि वह समाज, अस्मिता, गौरव और राष्ट्र के पुनर्जागरण के लिये पवित्र तथा नैसर्गिक अभियान भी है।

प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि नये भारत के निर्माण के लिये सामूहिक संकल्प किया जाये और मिलकर प्रयास किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसा नया भारत, जिसकी पहचान नई हो, जो दूरदर्शी हो और परंपरायें प्राचीन हों। एक ऐसा नया भारत, जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति, दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े, पूरी मानवजाति को दिशा दे। प्रधानमंत्री ने कहा, "जहां भी चुनौतियां हैं, वहां आशा के साथ भारत मौजूद है, जहां भी समस्या है, वहां भारत समाधान देता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई आपूर्ति श्रृंखला के बीच आत्मनिर्भरता की उम्मीद तक, वैश्विक शांति और संघर्षों के बीच शांति के लिये एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक, भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि आज, जनभागीदारी के बढ़ने के साथ सरकार के काम करने और समाज के सोचने का तरीका बदल गया है। आज, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्ट–अप प्रणाली है, जिसका नेतृत्व भारत के युवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम सॉफ्टवेयर से लेकर अंतरिक्ष तक, एक नये भविष्य के लिये तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। हमारे लिये संस्कार का अर्थ है दृ शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता! हमारे लिये संस्कार का अर्थ है दृ समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य! हम अपना उत्थान करें, लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। यही भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का सार है और यही भारत की प्रकृति भी है।"

प्रधानमंत्री ने वडोदरा के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया और अपने निजी और राजनीतिक जीवन में इस स्थान के महत्त्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' के आधार पर वडोदरा विश्व आकर्षण का महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है, यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इसी तरह, पावागढ़ मंदिर भी दुनिया में सबको आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'संस्कार नगरी' वडोदरा भी पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, क्योंकि वडोदरा निर्मित मेट्रो कोचों का इस्तेमाल विश्वभर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि यही वडोदरा की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश के स्वतंत्रता संग्राम में मरने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हम देश के लिये जी सकते हैं। उन्होंने सवाल किया, "क्या 15 अगस्त, 2023 तक, हम नकदी लेन–देन समाप्त कर सकते हैं और क्या डिजिटल भुगतान को अपना सकते हैं? आपका छोटा सा योगदान छोटे व्यापारों और विक्रेताओं के जीवन में भारी बदलाव ला सकता है।" इसी तरह, स्वच्छता, सिंगल–यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और कुपोषण को रोकने के लिये भी संकल्प किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने काशी के घाटों की सफाई के लिये नगालैंड की एक बालिका के अभियान का भी उल्लेख किया। उस बालिका ने अकेले अभियान शुरू किया था और बाद में कई लोग उससे जुड़ते गये। इससे संकल्प–शक्ति का परिचय मिलता है। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि देश की सहायता करने के लिये बिजली बचाने या प्राकृतिक खेती को अपनाने जैसे छोटे उपाय किये जाने चाहिये।

अन्त्योदयी, आत्म निर्भर
जनकल्याणकारी अर्थ संकल्प

साधक राजकुमार

भारतीय जनता पार्टी उ0प्र0 में दूसरी ऐतिहासिक विजय के बाद सरकार ने प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने, आम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने, लोक कल्याण संकल्प पत्र को सिद्धि तक पहुंचाने वाला बजट सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने समावेशी विकास के शुभ लाभ सकल सुमंगलकारी बजट रखा। खन्नाजी ने बजट रखते हुए कहा कि 'वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परिक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो' इन लाइनों के साथ बजट की शुरूआत हुई। एक–एक कर किसान, नारी सशक्तिकरण, जल संरक्षण, जनसंख्या नियोजन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज बनाने के मूल संकल्प के साथ जब बजट रखा गया तो एक सर्वोत्तम प्रदेश का पाथेय इस बजट में दिखा। योगी जी ने कहा कि उ0प्र0 का अब तक का सबसे बड़ा बजट है सभी वर्गों के कल्याण, समग्र विकास का ''अर्थ संकल्प'' है। इस बजट को श्री केशव मौर्य जी ने नरेन्द्र मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आया बजट गाँव–गरीब के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया। श्री ब्रजेश पाठक जी ने अब तक के सबसे बड़ सर्व समावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री जी एवं उनकी सरकार को बधाई दिया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में नये भारत का निर्माण हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में ये बजट नये भारत नये प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। श्री सुनील बंसल ने बजट को गरीब कल्याणकारी सर्वहितकारी बजट बताया। अर्थ शास्त्रियों ने इस बजट को एक ट्रिलियन डालर की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ कदम बताया है।

इस बजट में सांस्कृतिक उत्थान की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में योगी सरकार ने और ऊँचाई पर पहुंचाने का संकल्प दिखाया है। अयोध्या, मथुरा, काशी का कायाकल्प पर मुहर लगायी है। जिसमें संत रविदास जी और संत कबीर जी, महर्षि वाल्मिकि जी, निषादराज गुह जी, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए राशि की व्यवस्था सराहनीय है।

कुल मिलाकर यह बजट नये भारत, नये प्रदेश के निर्माण को गति देने वाला है जिसकी चहुओर प्रसंशा हो रही है। बजट के मुख्य बिन्दु निम्न हैं।

प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रूपये) है। बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181.10 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

कानून व्यवस्था

उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल के लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र/शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। उ0प्र0 फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

किसान

16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रूपये से 77,530 करोड़ रूपये अधिक है। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। वर्ष 2022–2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित। वर्ष 2022–2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

वित्तीय वर्ष 2022–2023

वर्ष 2020–2021 के वास्तविक आँकड़े, वर्ष 2021–2022 के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक अनुमानों के तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं –

(₹ करोड़ में)

बजट का सार

	2020-2021 वास्तविक आँकड़े	2021-2022 बजट अनुमान	2021-2022 संशोधित अनुमान	2022-2023 बजट अनुमान
1. राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ	**296176.33**	**418340.44**	**378731.40**	**499212.71**
2. कर राजस्व *	226584.30	305740.30	275243.97	367153.76
3. करेत्तर राजस्व @	69592.03	112600.14	103487.43	132058.95
4. पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	**87993.60**	**87841.40**	**91286.40**	**91739.00**
5. ऋणों की वसूली	1134.73	2332.00	2332.00	2565.00
6. उधार और अन्य देयताएं (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम)	86858.87	85509.40	88954.40	89174.00
7. कुल प्राप्तियाँ (1+4)	**384169.93**	**506181.84**	**470017.80**	**590951.71**
8. राजस्व लेखे पर व्यय जिसमें	298543.46	395130.35	356624.21	456089.06
9. ब्याज अदायगियाँ	37428.48	43529.81	42504.25	45987.46
10. पूँजी लेखे पर व्यय जिसमें	80167.20	155140.43	127917.81	159429.92
11. पूंजीगत परिव्यय	52237.10	113767.70	96480.63	123919.85
12. ऋण की अदायगियाँ	26777.49	38868.54	28732.98	32563.29
(जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान सहित)	10000.00	10000.00	0.00	10000.00
13. कुल व्यय (8+10)	**378710.66**	**550270.78**	**484542.02**	**615518.98**
14. राजस्व बचत (1-8)	**-2367.13**	**23210.09**	**22107.19**	**43123.65**
15. राजकोषीय घांटा	**54622.11**	**90729.80**	**74745.64**	**81177.98**
16. प्रारम्भिक घाटा (15-9)	**17193.63**	**47199.99**	**32241.39**	**35190.52**

* इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्यॉंश सम्मिलित है।

@ इसमें राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान सम्मिलित है।

महिला

03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है। महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत यू.पी.एस.ई.ई.–2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप का वितरण। मिशन शक्ति कार्यक्रम हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

बाल कल्याण

शिशु मृत्यु दर में गिरावट। दस्तक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी। कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान। 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अनुमन्य। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि।

युवाओं के लिये

निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना में लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन का वितरण। आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण का लक्ष्य। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की धनराशि

प्रस्तावित। युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। खेलो इण्डिया 'एक जनपद–एक खेल' योजनान्तर्गत 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना की योजना।

रोजगार

प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियाँ। बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य।

मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन। वित्तीय वर्ष 2022–23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना करते हुए 03 लाख 97 हजार 28 उद्यम पंजीकृत और 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन। प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स का चयन। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन। चिकित्सा शिक्षा में लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति तथा लगभग 10,000 नये पद सृजित।

सामाजिक सुरक्षा

वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 4032 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। दिव्यांग भरण–पोषण योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण योजना हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित। मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर

अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग का गठन। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित। आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 560 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

चिकित्सा शिक्षा

प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित, वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से आच्छादित तथा 14 जनपदों मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2022 के अनुरूप एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान।

प्रदेश के 14 जनपदों में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये का प्राविधान।

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

आयुष

गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

राज्य सरकार की आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना। अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन के लिए प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

'लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022' की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना हेतु 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस–वे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेस–वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।

लोक निर्माण

सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रूपये 18 हजार 561 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 04 हजार 747 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। ग्रामों एवं बसावटों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये 01 हजार 965 करोड़ रूपये की व्यवस्था। ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रमुख/अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2600 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 1600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूँजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सिंचाई एवं जल संसाधन

बाढ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रू0 2751 करोड़ का बजट प्रस्तावित। तटबन्धों का निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ का बजट प्रस्तावित। जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ का बजट प्रस्तावित। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु रू0 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित। एल0टी0आई0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मध्यगंगा नहर परियोजना हेतु रू0 600 करोड़,

सरयू नहर परियोजना हेतु रू0 310 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु रू0 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 423 करोड़ एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु रू0 130 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

वर्ष 2021–2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 15,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 19,500 करोड़ रूपये की बजट प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान।

मुख्यमंत्री आर0 ओ0 पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

ग्रीश्म काल में ग्रामीण क्षेत्र में सायंकाल 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दिनांक 01 जनवरी, 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट।

विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रूपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना ''रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम'' भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है जिसे 03 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 5530 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जायेगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था।

आवास

निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ई0डब्लू0एस0 इकाईयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुये इसे 500 रूपये निर्धारित किया गया है। इससे ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी।

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 140 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 597 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।

वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।

नगर विकास

भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की शुरूआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रूपये प्रस्तावित।

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उक्त योजना हेतु अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रॉसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता– अमृत 2.0 के अन्तर्गत 2000 हजार करोड़ रूपये तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) योजना हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

केन्द्र स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रूपये तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 05 शहर सम्मिलित है। प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। महाकुम्भ मेला–2025 प्रयागराज के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना हेतु

215 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिये 500 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्वावित। त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 7000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक कल्याण संकल्प–पत्र, 2022 के क्रम में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 15463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2022–2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित।

पंचायती राज

पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्श 2022–2023 के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 1788 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना हेतु वर्श 2022–2023 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कृषि

नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबन्ध योजना के लिये 97 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर कैम्पस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 58 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दुग्ध विकास

वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।

जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

जनपद वाराणसी में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मत्स्य

मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिये निशादराज बोट सब्सिडी योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिये 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 120 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सहकारिता

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की "ब्याज अनुदान" योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

अयोध्या में सीपेट केन्द्र के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नये औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 जनपदों– प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेश घटक योजना संचालित किये जाने हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

हथकरघा बुनकरों की पराम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावरलूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिये जाने हेतु 'मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति–2021 के अन्तर्गत 03 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने और 20,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य।

बेसिक शिक्षा

वर्श 2022–2023 में परिशदीय विद्यालयों में ''स्कूल चलो अभियान'' के अन्तर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है।

समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

कक्षा–1 से 08 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता–मोजा हेतु 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

मध्याह्न भोजन योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

माध्यमिक शिक्षा

सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

संस्कृत शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने के लिये आधुनिक विशयों का समावेश करते हुये एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्श 2022–2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्रदेश में 75 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर।

छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑन लाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण

केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022–2023 में ''न्यू एज ट्रेड्स'' के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 25 करोड़ रूपये तथा संत कबीर संग्रहालय की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था। संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था। राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अयोध्या में जनसुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुँचमार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। ऑन लाईन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर बेवसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पर्यटन

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 03 करोड़ 50 लाख रूपये तथा उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

वन एवं पर्यावरण

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्श 2030 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्षाकाल–2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित। वर्ष 2022–2023 में सारनाथ डियर पार्क में वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य में गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद संरक्षण योजना, राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबन्ध की स्थापना योजना हेतु 03 करोड़ 77 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। शहीद अशफॉक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान, गोरखपुर, सोसाइटी हेतु कॉर्पस फण्ड की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 1672 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 479 करोड़ 07 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट प्लान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

न्याय

उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यो हेतु 705 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रूपये 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ा कर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 90 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

खाद्य एवं रसद

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक, एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिंडर रीफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

महिला एवं बाल विकास

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रूपये की सहायता पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्श 2022–2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। पुश्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोशाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजस्व

राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड हेतु 541 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोशीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 24 हजार 477 करोड़ रुपये (1,24,477 करोड़ रुपये) निर्धारित।

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 49 हजार 152 करोड़ रुपये (49,152 करोड़ रुपये) निर्धारित।

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29 हजार 692 करोड़ रुपये (29,692 करोड़ रुपये) निर्धारित।

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10 हजार 887 करोड़ रुपये (10,887 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022–2023

प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रूपये) है।

बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181.10 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित।

कुल प्राप्तियाँ 5 लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपये (5,90,951.71 करोड़ रुपये) अनुमानित। कुल प्राप्तियों में 4 लाख 99 हजार 212 करोड़ 71 लाख रुपये (4,99,212.71 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 67 हजार 153 करोड़ 76 लाख रुपये (3,67,153.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 20 हजार 655 करोड़ रुपये (2,20,655 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 46 हजार 498 करोड़ 76 लाख रुपये (1,46,498.76 करोड़ रुपये) सम्मिलित है

कुल व्यय 06 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये 6,15,518.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है। कुल व्यय में 04 लाख 56 हजार 89 करोड़ 6 लाख रुपये (4,56,089.06 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 24 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (24,567.26 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखे से 6 हजार करोड़ रुपये (6000 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 18 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (18,567.26 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित।

प्रारम्भिक शेष 40 हजार 550 करोड़ 03 लाख रुपये (40,550.03 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 21 हजार 982 करोड़ 77 लाख रुपये (21,982.77 करोड़ रुपये) अनुमानित।

राजस्व बचत 43 हजार 123 करोड़ 65 लाख रुपये (43,123.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ 97 लाख रुपये (81,177.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है।

इस ऐतिहासिक बजट पर कुल मिला कर देखा जाय तो यह विकास, विश्वास, बदलाव का बजट है जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। केन्द्र में मोदी सरकार के आठ वर्ष पूरे हो रहे हैं डबल इंजन की सरकार है देश प्रदेश में चुनौतियों से लड़कर एक विकसित प्रदेश बनाने का यह अर्थ संकल्प है। अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाना कोविड महामारी की वर्तमान चुनौतियों के बीच देश प्रदेश के आर्थिक भविष्य आत्म निर्भर भारत को बनाने का सपना खेती किसानी नवाचार की पहल के लिए यह बजट फल दायी सिद्ध होगा। आइये मिलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के द्वारा इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पहल में अपने को जोड़ें।

21वीं सदी के नए भारत का निर्माण हो रहा है: स्वतंत्र देव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह ने वर्ष 2022–23 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले इस ऐतहासिक बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी एवं पूरी टीम बधाई की पात्र है उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण हो रहा है। हमारे नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कैसा हो उस दृष्टी से यह बजट प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन लाने वाला साबित होगा। गत 5 वर्षों में प्रदेश को विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुंचाने के बाद अब आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाना है यह बजट उसकी नींव है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर इन सभी लोगों की आय कैसे बढ़े, कैसे वह गरिमापूर्ण व सम्मानजनक जीवन जीयें, कैसे वह सभी विकास की मुख्यधारा से जुड़े इसे सोच कर सभी नीतियां बनाई गई है। प्रदेश के विकास में अहम् भूमिका निभाने वाले युवा, महिला, किसान, व्यापारी समेत समाज के समाज के सभी वर्गों को महत्त्व दिया गया है। प्रदेश के आकांक्षी क्षेत्रों से आने वालें नौजवान साथियों के भविष्य की चिंता इस बजट में उचित रूप से की गई है। किसी भी प्रदेश को हर प्रकार से समृद्धशाली बनाने के लिए वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो निवेश और रोजगार के अवसर और भी अधिक बढ़ेंगे और इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह बजट तैयार किया है।

ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव में विकास की बहेगी अविरल गंगाः केशव

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। गरीबी उन्मूलन की यह बहुत बड़ी योजना है। ग्रामीण आजीविका मिशन से गांव में विकास की अविरल गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि बी सी सखी से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं ।श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग, विशेषकर ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए दिए कि वह आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता तथा गतिशीलता के साथ संचालित करें और हर योजना के बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया जाए और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन से ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं, इसके लिए योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिड–डे–मील में स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित कराने तथा अंतरविभागीय समन्वय बनाकर अन्य विभागों की लाभार्थी परियोजनाओं में समूहों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का प्लान बनाया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक योजना का गहनता के साथ परीक्षण और आडिट होना चाहिए। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज गन्ना संस्थान में उ०प्र०राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभागार में ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।इस अवसर पर आजीविका मिशन के सभी बिंदुओं के बारे में बिंदुवार व योजनावार प्रेजेंटेशन किया गया। बीसी सखी व अन्य योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं और समूहों की महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए और यह देखा जाए कि कहीं पर भी किसी का शोषण न होने पाए ।अच्छा कार्य करने वाली बीसी सखियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएं। बीसी सखी के चयन, प्रशिक्षण ,मुद्रा लोन, संकुल स्तरीय संगठन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ग्राम संगठन को प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सहित विभिन्न योजनाओं की उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण आबादी को घर–घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य प्रदेश की 58000 ग्राम पंचायतों में समूह सदस्यों से बीसी सखी चयन की कार्यवाही करते हुये 56875 उम्मीदवारों का चयन किया गया तथा 42092 बी सी सखियों को प्रशिक्षित किया गया और 36842 बीसी सखियों के समूहो को बीसी सपोर्ट फंड प्राप्त हुआ और 25541 बी.सी. सखियों द्वारा लेनदेन शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बी सी सखियों के कार्यों से लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बहुत ही सकारात्मक और सार्थक परिणाम निकल कर आए हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने बैंक खातों से धन निकालने और जमा करने में बीसी सखियों के सहयोग से बहुत बड़ी आसानी हुई है और उनका बैंक तक जाने–आने का समय व खर्चा बच रहा है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में दावों के निस्तारण में सरलता लाई जाए और इसके लिए जो भी प्रक्रियात्मक कार्रवाई करनी है, उसे किया जाए। ग्राम संगठन व संकुल स्तरीय संघ संगठन के विषय में जानकारी देते हुए बताया गया कि सामुदायिक शौचालयों का संचालन, स्कूल ड्रेस बनाने, आंगनवाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण, सूखे राशन का वितरण, पोषाहार बनाये जाने जैसे कार्य समूहो द्वारा किए जा रहे हैं। बी सी सखी के माध्यम से लगभग 3000 करोड़ का लेन देन बैंकों से कराया गया है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग की कई योजनाओं में समूहो की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा की हाईवे के किनारे वृक्षारोपण में 5 साल में समूह की प्रत्येक महिला को प्रति पेड़ औसतन रू 1500/– मिल सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बी सी सखियों के अवशेष चयन के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। बताया गया समूहो द्वारा 243 पुष्टाहार इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समूहों के माध्यम से ऐसी भी चीज बनाने का प्रयास किया जाए, जिसका विदेशों में निर्यात हो सके। उपमुख्यमंत्री ने विद्युत सखियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इनको और अधिक सक्रिय किया जाए। बताया गया कि विद्युत सखियों माध्यम से लगभग रु0115 करोड के विद्युत बिल जमा कराए गए हैं। लगभग 9000 विद्युत सखी क्रियाशील है और इसमें विद्युत सखियों को अच्छा कमीशन प्राप्त हुआ है। प्रदेश में 1840 उचित दर की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूह को किया गया है और 350 प्रक्रियाधीन है। उपमुख्यमंत्री ने कहा की गांवों में एक अतिरिक्त दुकान खोलकर उसका संचालन समूह को दिए जाने का प्रपोजल बनाया जाए। यह योजना बहुत ही कारगर और सफल सिद्ध हो रही है। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके नामों का सरलीकरण किया जाए, ताकि आम जनमानस उनको भली–भांति जान सके।

ई-एनर्जी का प्रयोग बढ़ाया जायः ए0के0 शर्मा

विकसित देश खासतौर से अमेरिका ने हमारे देश में कार्बन उत्सर्जन के मामले में ज्यादा दबाव नहीं बना पाया। मोदी जी के कारण ही जलवायु परिवर्तन की एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनी, जिससे आज विकासशील देश बिना दबाव के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक उम्मीदों के साथ ही हमारी जीवन पद्धति और संस्कृति ऐसी है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को ज्यादा बल नहीं मिलता। हम प्रकृति के साथ तदात्म स्थापित करते हुए उसके मूल तत्व को नुकसान पहुंचाये वगैर, इसकी रक्षा करते हुए जीवन जीते हैं। फिर भी हम सभी कार्बन के दुष्प्रभावों को कम करने तथा बढ़ते हुए तापमान को नियंत्रित करने के लिए अभी से इसकी शुरूआत करनी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण व देश की आर्थिक उन्नति के लिए हम सभी अनावश्यक बिजली के उपयोग से बचें। कार्बन के शून्य उत्सर्जन की दिशा में स्टेट एनर्जी एफिशियन्सी एक्शन प्लान पर स्टेक होल्डर की सलाह हेतु होटल फार्चून पार्क हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला को आज बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सम्मुख ग्लासगो, अमेरिका में हुये सीओपी–26 सम्मेलन में 'पंचामृत' कार्यक्रम के तहत 05 मूल विषयों पर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसके तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी कर 01 लाख टन तक कम की जायेगी और वर्ष 2070 तक देश में कार्बन का शून्य उत्सर्जन प्राप्त होगा, इसके लिए हमें थर्मल ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से ऊर्जा उत्सर्जन को बढ़ावा देना होगा, जिसके लिए केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है। वर्ष 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा और यह लगभग 500 गेगावाट तक होगा। इसी प्रकार प्रदेश वर्ष 2030 तक 40 हजार मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से होने का लक्ष्य है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ताप को नियंत्रित करने के लक्ष्य को सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पूरा किया जाना है। उ0प्र0 में नेडा, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस पर कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 04 क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं जिसमें कृषि, यातायात, एमएसएमई और भवन निर्माण के क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना है। लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि हम सभी अपने जीवन में पेड़–पौधा जरूर लगाये साथ ही सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर सकें। सभी किसान और हाउस होल्डर स्वयं बिजली पैदाकर अतिरिक्त बिजली से मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसी प्रकार खेती–बाड़ी में माइक्रोईरिगेशन, ड्रिपस्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग कर भी बिजली की बचत की जा सकती है। इसी प्रकार यातायात के क्षेत्र में भी ई–एनर्जी का प्रयोग किया जा सकता है। उद्योग और एमएसएमई क्षेत्रों को भी ऊर्जा दक्ष बनाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र उ0प्र0 ऊर्जा दक्ष हो जाये तो विश्व के साथ–साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ी

उपलब्धि। कम ऊर्जा खपत करके किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। इस पर मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली खपत हल्का करने के चक्कर में चाइना का बल्ब खरीदकर न लगा लेना।

कार्यक्रम में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरूण कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक है कि कार्बन उत्सर्जन को समय रहते नियंत्रित कर लिया जाये, इससे बढ़ती हुई बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्बन के ज्यादा उत्सर्जन से गर्मी बढ़ रही है जिसके लिए जरूरी है कि बिजली की कम खपत वाले उपकरणों का उपयोग किया जाये। परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी पेड़ लगाना चाहिए। किसान भी अपनी खेत की मेड़ पर पेड़ लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने सभी से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिजली बचाने पर बल दिया और कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों के प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति का संरक्षण होगा साथ ही देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और समाज का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जूझ रहा है जिसे हम ऊर्जा दक्षता के बल पर इससे बच सकते हैं।

कार्यक्रम की शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री ए0के0 शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि श्री अरूण कुमार सक्सेना द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा राष्ट्रगान से हुआ। सभी अतिथियों को पौधा भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वन व पर्यावरण श्री मनोज सिंह, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री एम0 देवराज, सचिव ऊर्जा श्री पंकज कुमार, सचिव पर्यावरण श्री आशीष तिवारी, विशेष सचिव नेडा श्री भवानी सिंह खंगारावत सहित विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित थे।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान से स्वरोजगार सृजन

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे–बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करने, विकास, हस्तशिल्प की कला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्राथमिक बिन्दुओं में से एक ''विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना'' दिनांक 26.12.2018 से संचालित की गई है। इस योजनान्तर्गत कारीगरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक ऋण/आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के मजदूरों/कारीगरों के विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चालू की गई है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न बैकों को आवेदन प्रेषित कर ऋण उपलब्ध कराये गये हैं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए तथा उ0प्र0 का निवासी होना चाहिए। पिछले वर्षों में आवेदक द्वारा सरकार से टूलकिट्स योजना संबंधी कोई लाभ प्राप्त न किया हो। पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा, कोई भी इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए विभागीय बेवसाइट पर ऑनलाइन फार्म भरना होता है। जिसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक एकाउन्ट नम्बर, फोटो आदि अभिलेख संलग्न करना पड़ता है।

प्रदेश में विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभार्थियों ने अपना स्वरोजगार स्थापित कर लिया है। उनकी आर्थिक

प्रगति हो रही है। ऐसे लाभार्थी अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्रदेश में सरकार ने वर्ष 2021–22 तक बढ़ई ट्रेड के अंतर्गत 18040, दर्जी ट्रेड के अंतर्गत 42471, टोकरी बुनकर ट्रेड के अंतर्गत 5975, नाई ट्रेड के अंतर्गत 13135, सुनार ट्रेड के अंतर्गत 5910, लोहार ट्रेड के अंतर्गत 11164, कुम्हार ट्रेड के अंतर्गत 8222, हलवाई ट्रेड के अंतर्गत 21090, मोची ट्रेड के अंतर्गत 5824, राजमिस्त्री ट्रेड के अंतर्गत 10811, हस्तशिल्पी ट्रेड के अंतर्गत 770 लोगों को प्रशिक्षण देते हुए टूलकिट्स वितरण व ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इस योजना के अंतर्गत आच्छादित पारम्परिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को श्रम विभाग द्वारा जारी अर्धकुशल श्रमिक के मजदूरी के आधार पर मानदेय दिया जाता है। वर्तमान में रू0 250/– प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन के अनुसार मानदेय दिया जाता है। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण किया जाता है। उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं टूलकिट प्राप्त कर चुके लाभार्थियों में से ऋण सुविधा हेतु इच्छुक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब तक इस योजनान्तर्गत लगभग 66300 लाभार्थियों को रू0 372.00 करोड़ मुद्रा

इस प्रकार अब तक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न ट्रेडों में कुल 143412 लाभार्थियों को लाभान्वित कराकर उन्नत किस्म के टूलकिट प्रदान करते हुए रोजगार से लगाकर आत्मनिर्भर बनाया गया है।

जयंती दिवस – 28 मईपर विशेष

वीरसावरकर : तेज, तारुण्य एवं तिलमिलाहट की प्रतिमूर्ति

डॉ0 पवन सिंह

"मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ मदन, मुझे तुम पर गर्व है. सावरकर तुम्हें मेरी आँखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही,बिल्कुल नहीं मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है , तुमने गीता के स्थितप्रज्ञ को साकार कर दिया है मदन" न जाने ऐसे कितने ही जीवन है जो सावरकर से प्रेरणा प्राप्त कर मातृभूमि के लिए हस्ते हस्ते बलिदान हो गए. अपने महापुरुषों का स्मरण व सदैव उनके गुणों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते रहना, यही भारत की श्रेष्ठ परंपरा है. ऐसे ही अकल्पनीय व अनुकरणीय जीवन को याद करने का दिन है सावरकर जयंती।

यहां दीप नहीं जीवन जलते है

स्वातंत्र्य विनायक दामोदर सावरकर केवल नाम नहीं, एक प्रेरणा पुंज है जो आज भी देशभक्ति के पथ पर चलने वाले मतवालों के लिए जितने प्रासंगिक हैं उतने ही प्रेरणादायी भी. वीर सावरकर अदम्य साहस, इस मातृभूमि के प्रति निश्छल प्रेम करने वाले व स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला अविस्मरणीय नाम है. इंग्लैंड में भारतीय स्वाधीनता हेतु अथक प्रवास,बंदी होने पर भी अथाह समुद्र में छलांग लगाने का अनोखा साहस,कोल्हू में बैल की भांति जोते जाने पर भी प्रसन्ता, देश के लिए परिवार की भी बाजी लगा देना, पल –प्रतिपल देश की स्वाधीनता का चिंतन व मनन, अपनी लेखनी के माध्यम से आमजन में देशभक्ति के प्राण का संचार करना, ऐसा अदभुत व्यक्तित्व था विनायक सावरकर का. सावरकर ने अपने नजरबंदी समय में अंग्रेजी व मराठी अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें मैजिनी, 1857 स्वातंत्र्य समर, मेरी कारावास कहानी, हिंदुत्व आदि प्रमुख है.

सर्वत्र प्रथम कीर्तिमान रचने वाले सावरकर

सावरकर दुनिया के अकेले स्वातंत्र्य योद्धा थे जिन्हें दो–दो आजीवन कारावास की सजा मिली, सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 का प्रथम स्वतंत्रतासंग्राम को दो–दो देशों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। सावरकर पहले ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वे पहले स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने वापस ले लिया। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोक दिया गया। वीर सावरकर ने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे तात्कालिक राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने माना। उन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। वे ऐसे प्रथम राजनैतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी (फ्रांस) भूमि पर बंदी

बनाने के कारण हेग केअंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला पहुँचा। वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही जिन्होंने अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। दुनिया के वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंदमान के एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएँ लिखीं और फिर उन्हें याद किया। इस प्रकार याद की हुई दस हजार पंक्तियों को उन्होंने जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा।

काल कोठरी के ग्यारह साल व सावरकर

क्या मैं अब अपनी प्यारी मातृभूमि के पुनः दर्शन कर सकूंगा? 4 जुलाई 1911 में अंदमान के सेलुलर जेल में पहुँचने से पहले सावरकर के मन की व्यथा शायद कुछ ऐसी ही रही होगी। अंदमान की उस काल कोठरीमेंसावरकर को न जाने कितनी ही शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी होगी,इसको शब्दों में बता पाना असंभव है. अनेक वर्षो तक रस्सी कूटने, कोल्हू में बैल की तरह जुत करतेल निकालना, हाथों में हथकड़ियां पहने हुए घंटों टंगे रहना,महीनों एकांत काल–कोठरी में रहना और भी नजाने किसी –किस प्रकार के असहनीय कष्ट झेलने पड़े होंगे सावरकर को. लेकिन ये शारीरिक कष्ट भी कभी उस अदम्य साहस के प्रयाय बन चुके विनायक सावरकर को प्रभावित न कर सके. कारावास में रहते हुए भी सावरकर सदा सक्रियबने रहे. कभी वो राजबंदियों के विषय में निरंतर आंदोलन करते , कभी पत्र द्वारा अपने भाई को आंदोलन की प्रेरणा देते, कभी अपनी सजाएँ समाप्त कर स्वदेश लौटने वाले क्रांतिवीरों को अपनी कविताएं व संदेश कंठस्थ करवाते। इस प्रकार सावरकर सदैव अपने कर्तव्यपथ परअग्रसर दिखाई दिए. उनकी अनेक कविताएं व लेख अंदमान की उन दीवारों को लांघ कर 600 मील की दूरी पार करके भारत पहुँचते रहे और समाचार पत्रों द्वारा जनता में देशभक्ति की अलख जगाते रहे।

समरसता व हिंदुत्व के पुरोधा

सन 1921 में सावरकर को अंदमान से कलकत्ता बुलाना पड़ा. वहां उन्हें रत्नागिरी जेल भेज दिया गया. 1924 को सावरकर को जेल से मुक्त कर रत्नागिरी में ही स्थानबद्ध कर दिया गया. उन्हें केवल रत्नागिरी में ही घूमने –फिरने की स्वतंत्रता थी. इसी समय में सावरकर ने हिंदू संगठन व समरसता का कार्य प्रारम्भ कर दिया। महाराष्ट्र के इस प्रदेश में छुआछूत को लेकर घूम – घूमकर विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान देकर धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टि से छुआछूत को हटाने की आवश्यकता बतलाई। सावरकर के प्रेरणादायी व्याख्यान व तर्कपूर्ण दलीलों से लोग इस आंदोलन में उनके साथ हो लिए. दलितों में अपने कोहीन समझने की भावना धीरे–धीरे जाती रही और वो भी इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसा गर्व का भाव जागृत होना शुरू हो गया. सावरकर की प्रेरणा से भागोजी नामक एक व्यक्ति ने ढाई लाख रूपए व्यय करके रत्नागिरी में 'श्री पतित पावन मंदिर' का निर्माण करवाया। दूसरी और सावरकर ने ईसाई पादरियों और मुसलमानों द्वारा भोले भाले हिंदुओं को बहकाकर किये जा रहे धर्मांतरण के विरोध में शुद्धि आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। रत्नागिरी में उन्होंने लगभग 350 धर्म –भ्रष्ट हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया।

युवाओं के सावरकर

सावरकर का जीवन आज भी युवाओं में प्रेरणा भर देता है. जिसे सुनकर प्रत्येक देशभक्त युवा के रोंगटे खड़े हो जाते है. विनायक की वाणी में प्रेरक ऊर्जा थी. उसमें दूसरों का जीवन बदलने की शक्ति थी. सावरकर से शिक्षा – दीक्षा पाकर अनेकों युवा व्यायामशाला जाने लगे, पुस्तकें पढ़ने लगे. विनायक के विचारों से प्रभावित असंख्य युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ गया. जो भोग – विलासी थे, वे त्यागी बन गए. जो उदास तथा आलसी थे, वे उद्यमी हो गए। जो संकुचित और स्वार्थी थे, वो परोपकारी हो गए। जो केवल अपने परिवार में डूबे हुए थे, वे देश–धर्म के संबंध में विचार करने लगे. इस प्रकार हम कह सकते है कि युवाओं के लिए सावरकर वो पारस पत्थर थे, की जो भी उनके संपर्क में आया वो ही इस मातृभूमि की सेवा में लग गया।

सावरकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व उसके बाद भी उसकी रक्षा हेतु प्रयास करते रहे. इसलिए उनका नाम '**स्वातंत्र्य सावरकर**' अमर हुए।

जयंती दिवस पर उस हुतात्मा को शत–शत नमन ...

लखनऊ, मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उ0प्र0 सरकार मंत्रिमंडल के साथ...

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
मई द्वितीय अंक 2022 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

निर्माणों के पावन युग में;

वसुधा का कल्याण न भूलें!

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी